The House re-assembled after lunch at twenty-four minutes past two of the clock

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair].

SHORT DURATION DISCUSSION

Situation arising due to drought and floods in various parts of the country

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, let us take up the Short Duration Discussion. Mr. Jayantilal Barot will initiate the discussion.

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): माननीय उपसभापति जी, देश में आई बाढ़ और सूखे के बारे में अल्पकालिक चर्चा शुरु करने का जो आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। आजकल उत्तर भारत में बाढ़ के कारण बहुत से प्रदेशों में कई गरीब ....(व्यवधान)....

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, the Minister who is dealing with this subject is not here. Only the Minister of HRD is here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two Cabinet Ministers sitting here.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Is the Minister of HRD going to reply to this debate?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister concerned is coming.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: But...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Finance Minister is also here. Why do you worry?

श्री जयन्ती लाल बरोट: जी, यहां सदन में सरकार का प्रतिनिधित्व हैं, कैबिनेट मंत्री जी हैं। तो मैं कह रहा था, पूरे देश के कई प्रदेशों में बाढ़ भी आई हैं और कई प्रदेशों में सूखा भी हैं जब यह बाढ़ आती हैं, तब भी और जब सूखा होता हैं, तब भी केन्द्र सरकार की ओर से भी सभी राज्य कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं। मैं मानता हूं कि पानी एक ऐसी चीज़ हैं, जिसके बिना जीवन चल सकता नहीं हैं – पानी नहीं होता हैं, तो भी नहीं जी सकते हैं तथा पानीं हो और ज्यादा हो, तो भी लोग जी नहीं सकते हैं। पिछले कई सालों में इतना पानी नहीं गिरा हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, बाकी कई प्रान्तों में, जितना इस साल गिरा हैं। मैं अपने गुजरात की बात करूंगा। सिर्फ 24 जून से 3 जुलाई तक पूरे सीजन में होने वाली बारिश 5,6,7 दिन में एक साथ गिरी, जिसके कारण हमारे गुजरात के 11 जिलों में, 225 तहसीलों में बाढ़ आई और इस बाढ़ के कारण मैं मानता हूं कि पूरे गुजरात में 250 से ज्यादा स्टेट हाइवें, नेशनल हाइवे और एक्सप्रैस हाइवेज को भी नुकसान हुआ हैं। उसी तरह बडौदा महानगर में, सूरत महानगर में और ग्रामीण जिलों में 3 फुट से 15 फुट तक पूरा पानी

भरा हुआ था। हमारे माननीय गृह मंत्री जी एरियल सर्वे में आए थे, उन्होंने गुजरात का दौरा किया, उस समय भी पूरे गुजरात की जितनी जमीन हैं, उसमें से 70 परसैंट जमीन में पानी भरा हुआ था, लोग बेघर हो गए थे। मैं इसके साथ यह भी कहूंगा कि गुजरात सरकार के डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ओर से, राज्य सरकार के तंत्र की ओर से, मंत्रिमंडल की ओर से जागृति दिखाकर पूरे क्षेत्र की जानकारी करने के कारण 3 लाख लोगों को आगाह करके, कैम्प बनाकर उनके रहने का इंतजाम करवा दिया गया। 4 से 5 लाख लोग, जो NGO's थे, स्वैच्छिक संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं थीं और बाकी लोगों ने अपनी- अपनी तरह अलग –अलग जगह स्थान बनाए रखा। इस बाढ़ एक कारण , अगर सरकार की जागृति नहीं होती, अगर इस तंत्र ने काम नहीं किया होता, तो बहुत जान-माल का नुकसान होता। गुजरात में 200 मानवों की मूत्यृ हुई, 7,000 से ज्यादा पशुओं की मृत्युहुई हैं। गुजरात में छोटा-मोटा गिनते-गिनते 9,000 करोड़ के आसपास का खर्चा, नुकसान हुआ हैं। गुजरात में पिछले पांच –छः साल साल से न जाने क्या हो रहा हैं कि कभी बाढ़ आती हैं, कभी भूंकप आता हैं, कभी साइक्लोन आता हैं, कुछ न कुछ ऐसा होता हैं जिससे कि गुजरात तकलीफ में रहता हैं। हम मांग करते हैं कि गुजरात आजकल देश में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा हैं, लेकिन ऐसी तकलीफो के कारण कहीं न कहीं गुजरात को दिक्कतें होती रहती हैं, इसलिए हम केन्द्र सरकार से एक विनती करते हुए मांग करते हैं कि सूनामी जो आया था, उस सूनामी ने, बिना कहे , एक झटके में देश के कई राज्यों में नुकसान किया था, उसी तरह यह आकाशी सूनामी गिरी हैं और गुजरात को इसने तबाह कर दिया हैं। हम मांग करते हैं कि केन्द्र सरकार की ओर से गुजरात और बाकी जिन प्रान्तों पर यह आकाशी सूनामी गिरी हैं, जहां बर्बादी हुई हैं, जहां जान की हानि हुई हैं, जहां पशुओं की मृत्यु हुई हैं, जहां हमारे घर बर्बाद हुए हैं, जहां किसानों की खेती बर्बाद हो गई हैं, उन सबके लिए सूनामी के नार्म्स लागू किए जाएं और उन राज्यों को, उन गरीब लोगों को, उन दलित लोगों को, उन आदिवासियों के निवास के लिए भी वही नार्म्स लगाकर उनके पुनर्वसन के लिए यहां से भी मदद दी जाए, ऐसी मैं विनती के साथ मांग कर रहा हूं।

साथ ही साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य की नदियां एक साथ 10-10, 15-15 दिन तक 15-15 फुट खतरे के निशान से ऊपर चलती थी। उसी तरह यहां से लश्कर की टुकडियां भी आइ, सभी मदद करने वाली संस्थाएं काम में लगीं, लेकिन यदि उस दिन आपने देखा होता तो पांच-पांच किलो मीटर तक पूरा ट्रैफिक जाम था,सड़कें टूट गई थीं। जो लोग घर से निकले थे, दस-दस दिन तक अपने घर तक नहीं पहुंच सके थे, इसी दिक्कत में लोग बहुत अधिक फंसे थे, ऐसे गुजरात की जनता ने बहुत अधिक सहायता की। मैं मानता हूं कि जो संस्कार हमारे देश के हैं, जो संस्कार हमारे हिन्दू समाज की संस्कृति के हैं, उस आधार पर जहां तकलीफ होती हैं, जहां दिक्कत होती हैं, जहां लोग दुखी होते हैं, वहां पर अन्य लोग पहुंच जाते हैं और सबकी सेवा करते हैं, सबका काम करते हैं, सबको आश्रय देते हैं और सबको ठीक प्रकार से रखते हैं। यह जो हमारी संस्कृति हैं, हमारे देश का भ्रातृभाव हैं, उसी आधार पर मैं कहता हूं कि जब सुनामी आया तब गुजरात ने भी अन्य प्रान्तों में हवाई मार्ग से 130 टन, सड़क मार्गो से 46 टन से 500 टन एवं रेलवे मार्ग से 1915 टन सहायता भेजी थी। एक तरह मैं मानता हूं कि हमारे देश में सहायता करने वाले लोग, सहायता करने वाली संस्थाएं एवं अन्य भी बहुत से लोग काम करते हैं।

आपको जानकारी होगी कि अतिवृष्टि के कारण हमारे गुजरात के 6719 गांव और 57 नगर, नगर पालिकाएं पूरे पानी में डूबे हुए थे, इस कारण बिजली चली गई थी। बिजली भी पांच-छः दिन में सभी जगह पर शुरु कर दी गई । पीने के पानी की सप्लाई भी 5752 गांवो में खत्म हो गई थी, उसे भी तीन दिन में पूरे गुजरात में शुरु कर दिया गया। जो पंचायत की 1561 सड़कें थीं, वे भी सब टूट गई थीं, लेकिन जल्द ही पुनः शुरु हो गई। आज केवल आठ सड़कें ऐसी हैं जहां हम यातायात शुरू नहीं कर सके हैं क्योंकि वहां पानी के कारण बहुत नुकसान हुआ हैं। रेलवे लाइन भी वहां पर कम से कम दो-तीन जगह पर इतनी अधिक डूब गई थी, जिस कारण एक हफ्ते तक अहमदाबाद-दिल्ली-मुम्बई की रेलें भी नहीं चल सकती थीं, इस प्रकार रेलवे को भी बहुत नुकसान हुआ हैं। यदि आपने टी.वी. में डाकोर रेलवे स्टेशन देखा हो, जहां पूरी रेल खडी थी, जिसमें 450 से अधिक यात्री सवार थे और जिसमें पांच से छः फुट पानी भर गया था और स्टेशन के साथ पूरा एरिया पानी से भरा हुआ था, लोगो की हालत इतनी खराब थी, लेकिन मैं गुजरात की बहादुर जनता का अभिवादन करता हूं। जिस तरह राज्य सरकार ने समझ से काम लिया और जिस तरह से लोगों के पास इस सबकी जानकारी पहुंचाई,उन सभी तक मदद पहुंचाई, वह तारीफ के योग्य हैं। मैं आपको थोडी सी जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से 19, 950,63 व्यक्तियों को तुरंत 18,95,19,108/- रुपये नकद बांट दिए गए थे। 2,39,509 कुटुम्बों को 24,65,83,909/- रुपये की सहायता घर बनाने के लिए दी गई थी। नागरिक परिवहन निगम के द्वारा भी जिनका सब कुछ बह गया था, उन परिवारों के लिए 1,27,980 राशन की किट्स बना कर बांटी गई जिससे कि उनका सामान 15 दिन तक चल सके। इसी तरह जिन दो-तीन दिनों मे भारी बरसात के कारण बहुत अधिक तकलीफ थी, उन दिनो में 47,68,980 फूड पैकेट्स एवं उतने ही पानी के पाउच एवं बोतलो की सप्लाई भी की गई थी। एअर फोर्स से आए हेलीकॉप्टर्स के द्वारा 2,26,820 फूड पैकेट्स एवं पानी के पाउच व बोतलें भी वितरित की गई थीं। इस आपदा में लश्कर की ओर से एवं अन्य व्यक्तियों की ओर से हैंलीकॉप्टर्स एवं नाव इत्यादि के द्वारा सबको बचाने में मदद पहुंचाई गई । मेरा आग्रह यह हैं और हम मांग करते हैं कि यदि इस प्रकार किसी भी राज्य में कोई तकलीफ हो , बाढ़, या सूखा हो, उस राज्य में हमारी सरकार की ओर से थोड़ा ध्यान दिया जाए एंव उदार सहायता करने के नॉर्म्स के कारण जो क्षेत्रों में काम करने वाले किसान एवं मज़दूर हैं, कृषिकार हैं अथवा बाकी जो गरीब आदिवासी लोग हैं, जिन्हें दो-तीन या पांच वर्ष में कभी-न-कभी बाढ या बारिश में इस प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं उनको परमानेंट रहने के लिए निवास का भी इंतजाम हो जाए तथा उनकी रोटी-रोजी के लिए भी इंतजाम हो सकें और उनके लिए हम सब कुछ कर सकें। आजकल सरकार की ओर से, जो नुकसान हुआ था उन सबका सर्वे भी हो गया हैं। एक लाख चौव्वन हजार का सर्वे हुआ था, उसमें से 62 हजार लोगों को जो सरकार की तरफ से मदद थी, वह भी देना शुरू हो गया हैं। साथ ही मेडिकल टीम भी पूरी तरह से काम कर रही हैं। मुझे दो चीज कि आपसे जानकारी करनी हैं कि माननीय गृह मंत्री जी तुरन्त ही वहां पर आए थे, उन्होंने भी दौरा किया था। हमारे रक्षा मंत्री श्री मुखर्जी और सोनिया जी भी वहां पर आई थीं। इन लोगों ने भी वहां दौरा किया था। सब लोगों ने देखा हैं कि गुजरात के ऊपर आकाशी बरसात की क्या आफत आई थी। इसलिए हम अपनी मांग को पुनः दोहराते हुए मांग करते हैं कि सुनामी के नार्म्स के मुताबिक गुजरात सरकार को मदद दी जाए। पाचं सौ करोड़ रुपया एड्हॉक डिक्लेयर किया था। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता हैं कि

कैलेमिटी रिलीफ फंड जो हर साल स्टेट को दिया जाता हैं, वह 52 करोड़ रुपया भी सरकार ने बहुत देरी से 4-7 को दिया। हमारे यहां सुनामी 24 तारीख को शुरु हुई थी, तीन तारीख तक बारिश हुई, 4 तारीख को दिया नहीं था। हमारी मांग होने के बावजूद वह पैसे नहीं दिए गए। लेकिन हर साल केन्द्रीय सरकार की हर राज्य को जो कैलेमिटी रिलीफ फंड दिया जाता हैं वह पहले से रिलीज कर देना चाहिए। बारिश या कुछ भी हो तो वह पैसा काम में आ सकें। बाद में पांच सौ करोड़ रुपए का जायरात हो गया। जायरात होने के बाद भी लोग कहते हैं कि पांच सौ करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन पांच सौ करोड़ रुपया जो दिया जब जायरात हुई उसके 15 दिन बाद गुजरात सरकार को दिया गया। मैं मानता हूं कि इस तरह जायरात होते ही 24 घंटे में या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में जिस स्टेट को सहायता देने के लिए डिक्लेयर किया हो उसको पहुंचा देना चाहिए, केवल पॉलिटिकल भाषण करना या यह बोलना कि हमने दिया हैं, यह बात अच्छी नहीं हैं। इसलिए पहले देना चाहिए और बाद में बोलना चाहिए कि हमने सब को दे दिया हैं।

उसी तरह जहां पर सूखा हैं क्योंकि हमारे गुजरात में 11 जिलों में 225 तहसील में बाढ़ थी, उसी तरह 35 या 36 तहसीलें ऐसी हैं जहां पर सूखा हुआ हैं, वहां पानी भी नहीं हैं। आजकल पीने के पानी की भी दिक्कत हैं और घास की भी दिक्कत हैं। पशु पालन के लिए भी लोगों को दिक्कत हैं । मैं आपसे विनती करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस अकाल को जो वहां पर सूखा होता हैं, उस सूखे की परमानेंट विदाई करने के लिए हमारी राज्य सरकार की एक योजना हैं, नर्मदा का, जो बारिश होता हैं उस सर्प्लस पानी को लेकर के सुजला में बाकी डेम में भरने के लिए हाई लेविल कैनाल में से दूसरी कैनाल निकाल करके गुजरात के 10 जिलों में कैनाल द्वारा पानी पहुंचाने की एक योजना रखी हैं। यह योजना पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से उसमें भी ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए क्योंकि यह सूखा गुजरात के लिए हमेशा कुछ क्षेत्रों में प्रोब्लम रहती हैं। जैसे कच्छ, मेहसाना, पाटिन डिस्ट्रिक्ट में सूखा हमेशा आता हैं। हर 10 साल में 5 से 1 0 साल सूखा रहता हैं। वहां लोगों तथा पशुओं को रहने के लिए दिक्कत होती हैं। सूखे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से मान्यता दी जाए और आर्थिक सहायता देकर तुरन्त पूरी मदद करें। इसलिए आप उसमें सहायता करें। इसी बात के साथ, मैं आपका धन्यवाद करके अपनी बात को विराम करता हूं।

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak about the flood situation in the country. I have just heard my colleague, the hon. MP from Gujarat, who explained everything about Gujarat. In the meantime, Central Government has taken all steps in Himachal Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Bihar and other places in the country. I am residing in such a place where there are always floods. Last year, there was a tremendous flood in Assam. This was the most devastating flood in the history' of Assam in which twelve million people were displaced, large sectors of crops were damaged and road link of the North-East with the rest of India was totally cut off. But our hon. Prime Minister visited this site, and the UPA Chairman, hon. Soniaji, also visited this site. They have instituted a Task Force. The Minister in charge

of Flood Control is not here. But as a Ruling Party Member, I must say that though you have instituted this Task Force, but it is not yet implemented. Sir, I am observing one thing that in 1981, the Brahmaputra Board was instituted, but no concrete action has yet been taken in that regard. We had raised this issue at the time of NDA Government and I have already brought this to the notice of our Government as well, but there is no action. There is no permanent Chairman. It is like a White Elephant. I am saying it is nothing but a White Elephant. The Prime Minister has also got convinced about this and accordingly he formed this Task Force, but it is not yet implemented. J do not know what is the position at present.

Sir, on 21st July, 2005, there was another spate of floods in Assam in River Brahmaputra and its tributaries are over-flowing at Tezpur, Dhubri, Karimganj, Nematighat, Barpeta, etc. Assam has two Vallies. One is Barak Valley and another is Brahmaputra Valley. This time it affected 13 districts and 383 villages of Assam. There was great loss of human lives also. Approximately 34853 people were affected and the number of houses damaged was around 86. Not only the crop, but 21956 hectares of land was also badly damaged in it. The Central Government should find out some permanent solution to save Assam from the losses of lives, crops and economy of the State. Mere promises and allocation of funds is not the solution. Big promises from the Centre do come. The Centre has committed some money. I appreciate that our hon. Prime Minister has taken such steps. But I do not know why the Government is not allocating funds. The Finance Minister is here. I heard Shri Priyaranjan Dasmunsi, the Minister of Water Resources saying that there is no finance available to check erosion due to floods. There is no financial approval. Shri Priyaranjan Dasmunsi made a statement that he is facing a lot of problems from the Finance Ministry. Our Prime Minister and the UPA Chairman, Soniaji, are very much keen about the North-East, particularly, about the flood situation. I request the Finance Minister to kindly approve the fund required for this purpose. I also request the Minister of Water Resources to take care about the flood situation not only in Assam but also in other seven connected States.

With regard to the floods in Himachal Pradesh, I think there is some problem from China and Bhutan side. That is why floods occur in Assam, and, particularly, in Himachal Pradesh. So, I urge upon the Government to kindly examine all these things technically.

It will not be out of place to mention that a permanent, regular Chairman of Brahmaputra Board is yet to be appointed. I, therefore, urge upon the Central Government that floods in Assam should be declared a 'National Problem', and accordingly steps should be taken to combat the same. Mere survey of the flood-affected areas and big promises alongwith the fund allocation will not bring out any permanent solution. In the year 1950, in Assam, there was an earthquake. There was erosion in Brahmaputra and its tributaries. Since the 1950 earthquake when Brahmaputra had changed its directions, the river has eroded seven per cent of Assam's total areas and destroyed Rs. 21 Crores worth property and infrastructure of the State. So, Brahmaputra is devastating. It should be examined as to in what way these floods should be controlled. Only the Brahmaputra Board cannot control floods. For the last twenty years, I have been hearing about surveys, surveys and more surveys, but no action has been taken even today. So, I request the hon. Minister to take care of the issue because our leader, Dr. Manmohan Singh and Shrimati Sonia Gandhi have already instructed all the departments to look into the Assam floods in particular and the problems of the North-East. Thank you.

SHRI MATILM. SARKAR (Tripura): Thank you, Sir. I rise to participate in the discussion on floods and droughts.

First of all, I shall give a general idea about floods and droughts and then, I shall come to my home area, that is, the North-Eastern region. On an average, floods claim more than 1500 lives every year and ninety-four thousand heads of cattle, and there is a damage of about 1.2 million houses every year. The annual damage is about Rs. 1500 Crores every year. The *Rashtriya Barh Ayog* has estimated the expense of flood-prone area to be about 40 million hectares, and according to the *Ayog,* of these 40 million hectares, at least, 32 million hectares could be protected.

There is a Working Group and the Working Group has suggested some measures. The Working Group recommended an outlay of Rs. 10,631.84 Crores in the Tenth Plan in the State sector and about Rs. 3007.91 Crores in the Central sector. I do not know whether these figures have been taken into consideration by the Government as yet.

As regards drought, I would like to enunciate that the demand for water is increasing every year, day by day. In the year 2000, the demand was about 634 bcm and now, it has come up to about 1000 bcm. Every

year, there is an increase in the demand for water. This water is meant for irrigation and for other purposes. Rapid industrialisation is going on and that is also one reason why water is needed. That is why water is needed. Besides this, in other sectors also water is demanded, such as, consumption by industries, domestic consumption, as a source of energy to maintain ecological balance and to maintain the navigability of rivers. So, there is an increasing need of water. When this need is not fulfilled as we see in drought, we see crisis of water. Sir, last year, 7.66 million hectares of land was affected by floods, of which 3.55 million hectares was the cropped area. During this year, we have seen that the States of Gujarat, Madhya Pradesh, and Himachal Pradesh have suffered the most. Though the North-Eastern region is a generally flood-affected area, but this year the effect has not risen to such an extent. My question is: Why have we not succeeded, uptil now, in taking up a comprehensive plan to tackle this menace of floods and droughts? We know that there are drought-prone areas; we know that there are flood-prone areas. When sum and substance of these menaces are known to us and we have also got our engineers and scientists, if we make an attempt to take up a comprehensive plan to fight these two menaces - the twins of natural calamities, one being drought and the other flood - we can, at least, minimise these two menaces.

During the last year, our Tripura State was badly affected. Three people died due to flood and several thousands had to leave their houses and take shelter in camps. There were some sub-divisional towns which were on the threshold of flood. Our State Government had given a proposal to the Central Government to erect dams to safeguard these towns. Khowai, Sonamura, Kailasahar, etc., are major towns in the State where river over-flows and water floods these towns. I think, the Central Government would take up some of the projects. We have discussed it with the Water 8 Resources Minister, but prompt action should be taken in regard to these issues. We demanded Rs.75 Crores for flood-relief but we got only Rs.5 lakhs! Rupees 75 Crores was the demand and we got only Rs.5 lakhs. This should not happen. The reason of flood in the North-East is that rivers come from upstairs, that is, as regards West Bengal some rivers come from Bhutan. They cause floods in the North Bengal areas. Erosion takes place. In our State, we see that water goes down towards Bangladesh.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN) in the Chair]

Naturally, Bangladesh Government would take steps to save their towns and lands. Naturally, they will create some protective dams and this again creates blockage of water in our State. That is why, the Central Government has to take some initiative so that the two countries may sit together and see that water of one area does not create trouble for the other. Such is the case with Bhutan also. Sir, I would not like to go into the details of Gujarat, as it has already been narrated. There is loss of lives. More than 200 people have died and several towns have been flooded. I have the figures. Over 57 towns and more than 600 villages have been flooded. I would like to say that the Central Government should come forward with relief fund.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Matilalji, I don't want to stop you, but you have couple of minutes more.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, fund has already been provided. My question is : why was it flooded like that? There was a heavy rainfall. I agree. But, even then, the State Government should have already made some design to protect their cities and protect their land. As per the information that I have, I may give it here, the arbitrary permission of municipality to erect buildings, is one of the causes why the water was blocked, obstructed and the drainage was blocked. The construction of Express Highway and Narmada Canal has blocked the natural flow of water, and that is why, the water could not run speedily into the Bhuki River. Consequently, the overflowing of river has caused the flood. So, these are the measures to be taken by the State Government ahead of floods, as we are doing in our State to protect our towns. We are cleaning our drains and we are trying to divert the water. Every State is taking steps. Though there are heavy rains in Gujarat, but this menace has reached to this height only because of lack of effective steps. Now, finally, I would like to give some suggestions as regards the utilisation of relief funds. Care should be taken to see that the money should go to the poor people. When floods occur, everyone will say that he has suffered losses, that his crops have been spoiled and his house has been destroyed. But, care should be taken to see that the maximum benefit reaches the poor, who cannot afford for themselves, to those families which cannot afford for themselves. The real victim should get the benefit of this. Another point which I would like to mention here is that the Centre should extend all-out efforts for reconstruction where the damage has taken place heavily.

3.00 P.M.

Suppose school-buildings have been destroyed, water has entered into some market and the streets have fallen in bad condition, houses have been destroyed at large and the people have taken shelter on hillocks, in that case, this type of heavy floods cannot be handled by States alone. So, the Centre should take keen note of helping the States in this respect. The third point I would like to make is, funds for Employment Guarantee Scheme should be sanctioned extensively, both by the State Governments and the Centre, if the State Government thinks that the help from Centre is necessary. The Employment Guarantee Scheme should be extensively undertaken in the flood-affected States like Gujarat, Himachal Pradesh and others, so that people may not die of hunger. Once floods have put them into trouble, poverty should not put their lives further into trouble. *(Time-bell).* Lastly, I must say that when the relief fund is sanctioned, it is seen in some States, it is diverted without using it for the purpose for which it was sanctioned. We call upon the State Governments that whatever money they get from the Centre-our demand is that Centre should help them extensively-that money should not be diverted to other programmes. The fund should be utilised to take precautionary measures against the floods and to take up reconstruction work. With these words, I conclude. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Mr. P.G. Narayanan, you have got eight minutes.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, taking the whole scenario of our country, one part of our country is facing drought while the other part is getting affected by the floods. Now, we have floods in Assam, Gujarat, U.P. and Bihar. But, the southern part of India is still facing acute shortage of water. The peninsular rivers are likely to face the brunt of water problem. Peninsular rivers are mostly rain-fed rivers and once the monsoon fails, these rivers become dry. So, to avoid floods and droughts, we have to give a serious thought to linking of rivers of various regions of our country. After the Supreme Court directives, a Task Force was set up by the NDA Government on the linking of rivers. But, this Government is not serious in implementing the scheme of linking of rivers. This is not good for the development of our country. I also demand .that the Centre should enact a legislation to nationalise all the rivers so that petty and parochial considerations do not come in the way of implementing the worthwhile interstate water projects.

I wish to draw the attention of the House to a serious situation prevailing in the Cauvery Delta Region of Tamil Nadu. Lakhs of farmers in the Cauvery Delta Region are not able to go ahead with the cultivation of their short-term kuruvai paddy crop this year. Agricultural operations could not be undertaken for the fourth consecutive year because the State of Karnataka has not released the Cauvery water to the Mettur Dam in Tamil Nadu as per the Interim Order of the Cauvery River Water Dispute Tribunal. ...*{Interruptions)*....

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka) : Sir, already water has been released.

SHRI P.G. NARAYANAN : The Tribunal set up by the Supreme Court stipulates in its Interim Award weekly and monthly release of water from the Cauvery River by Karnataka. But Karnataka has not at all adhered to the weekly and monthly release of water prescribed in the Award. Sir, the Interim Order of the Cauvery River Water Dispute Tribunal has the force and effect of an order of the Supreme Court of India. Sir, when there was excessive rainfall in the catchment areas; when the rivers got flooded; when Karnataka was not able to hold water in the dams, they released the water to Tamil Nadu. ...*{Interruptions)*.... This is the fact. To put it in a nutshell, Karnataka has converted the Cauvery River flowing in the region....*(Interruptions)*....

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, he is misleading the House. We are releasing water from the Kabini Dam...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Narayanan, will you yield for a minute? Now both of them are fighting.

SHRI P.G. NARAYANAN: We are fighting for our right.

SHRI V. NARAYANASAMY: Karnataka has not released water as per the agreement. Let me make it very clear.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Mr. Narayanasamy, can you yield for a minute? It is true that water has been released from the Kabini Reservoir. There is no water in the dam. There is a severe drought. So we cannot release the water. But still we have been releasing water.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Will you please listen to me? This is one of the occupational hazards of being a Vice-

Chairman because I happen to appear for Karnataka. Therefore, the hon. Member is addressing me.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I would like to put one question to the hon. Member. They have sent a delegation. We also support the demand of Tamil Nadu. There is no doubt about it. But, Sir, Pondicherry is entitled to six TMC of water out of 205 TMC. Although Karnataka has released water, Tamil Nadu is not giving water to us. He has to answer this question.

SHRI G.K. VASAN: Actually, the Government has not taken proper steps. That is why farmers are suffering today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Let him speak.

SHRI P.G. NARAYANAN: The fact of the matter is the Karnataka Government has sabotaged several attempts by the Central Government to evolve a Distress Sharing Formula. This distress should be shared equally by Karnataka and other riparian States. Distress does not mean that they will keep the entire water with them. This is exactly what the Karnataka Government has been doing for the last several years. Sir, this year, there is no distress at all in Karnataka.

SHRI B.K. HARIPRASAD: He is misleading the House. There is a serious water problem in Karnataka..*(Interruptions)*... He cannot mislead the House like this. This is a very sensitive issue...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Have you given your name? ...*(Interruptions)*... Mr. Narayanan, don't answer him. You carry on.

SHRI P.G. NARAYANAN: This is the state of affairs. So, Karnataka has been stalling any move to resolve this issue amicably between these two States. After 18 years of bilateral and trilateral negotiations involving the Centre having failed to yield desirable results, the Tribunal was set up in 1980. It gave its Interim Award in 1992 which stipulated that Karnataka should release 205 TMC of water every year to Tamil Nadu. The Congress-ruled Karnataka Government, instead of implementing the Award, promulgated an Ordinance to nullify the implementation of the Award. The Supreme Court struck down this Ordinance saying that this attitude of the Karnataka Government posed a serious threat to the unity and integrity of the country...*(Interruptions)*...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): But they themselves said that the Karnataka Government was justified in not obeying the Interim Award. That was their stand.

SHRI P.G. NARAYANAN: Why is the Central Government not intervening in this?...*{Interruptions)...*

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: But you supported the Karnataka Government when our Government was in power.

SHRI P.G. NARAYANAN: During this year, even though some surplus water is flowing from the Kabini Reservoir to the Mettur Dam, as on 25.7. 2005, at the Mettur Reservoir, we received only 21.49 TMC feet of water as against the prescribed quantity of 45.80 TMC feet leaving a shortfall of 24.32 TMC feet of water. If only this quantity of 24.32 TMC feet had been released by Karnataka from its reservoirs, by this time the farmers of the Delta areas in Tamil Nadu could have started their agricultural operations. Now, we understand that Karnataka has comfortable storage position and so they can easily release water. But they are very adamant. They are defying the orders of the court, defying the orders of the CRA, defying everything. They are going against the Constitution of India...

SHRI B.K. HARIPRASAD: When there is no water, where is the point of going against the order?

SHRI P.G. NARAYANAN: The Prime Minister should intervene in this matter and prevail upon the Chief Minister of Karnataka to immediately release the balance of water. In this regard, our Chief Minister met the Prime Minister today morning and requested him to prevail upon the Karnataka Government to ensure the release of balance water. She has also demanded that the CRA should be convened immediately to discuss the matter and find out a proper solution. On the direction of the Supreme Court, the CRA was formed with the Prime Minister as its Chairman and the Chief Ministers of the four concerned States as its members. The job of the CRA is to implement the interim order of the Cauvery Water Dispute Tribunal. But the CRA has failed to implement the interim orders of the Tribunal because it has no power in this respect. The CRA was not able to finalise even the distress-sharing-formula. This is the state of affairs there. The Distress Water Sharing Formula and the Interim Award also stipulates... ...*{Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Let him speak. Please do not interrupt. Yes, Mr. Narayanan.

SHRI P. G. NARAYANAN: So, I demand that the Government should take strong steps to implement the orders of the Supreme Court, the Tribunal and help the State of Tamil Nadu.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): The same problem with my good friend, Mr. Hariprasad! We are the sufferers at the hands of Karnataka. Sir, my State happens to be the lower riparian State for both Krishna and Godavari rivers.

While thanking you for giving me this opportunity, I would like to draw the attention of the Government to the water problem. As narrated by my good friend, Mr. Narayanan, we have floods in some parts and drought in other parts of the country. The people at the helm of affairs should think over this matter and see to it that the water problem is solved. The NDA Government had constituted a task force under the leadership of Shri Suresh Prabhu on the interlinking of rivers. Just because it was the idea of the NDA Government, they want to put it into the cold storage. This is not fair. The idea at that time was to see to it that all the rivers are linked so that we do not have this situation of floods in some parts and drought in other parts. So, I would like to request the Government of India to see to it that the programme is continued and the good work done by Shri Suresh Prabhu is continued. Sir, as stated by me, we are the lower riparian State for both Krishna and Godavari rivers. Karnataka again is the problem for Andhra Pradesh also. They have nowadays become a bad neighbour for Tamil Nadu and Andhra Pradesh. ...*(Interruptions)*... Sir, he knows the practical problems of Andhra Pradesh. We have been fighting for our cause, right from Almatti. Water flows into Narayanpur; from there it flows into Jurala project of Andhra Pradesh. That is the first project in Andhra. The Krishna Water Dispute Tribunal award was violated on many occasions by Karnataka and we have been the sufferers. Being the lower riparian State...

SHRI B. K. HARIPRASAD: Why can't we accept the Bachhawat Commission's report. The Commission has given its report. They are not accepting it.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I hope my good friend will be given an opportunity. Rather than behaving like somebody in a quiz programme, he should get an opportunity to reply. I request the hon. Vice-Chairman to come to my rescue and allot some time to him so that he can reply. Sir, Mr. Hariprasad is very active; I know. But still, he

should have some sympathy towards Andhra Pradesh also. The people at the helm of affairs in Andhra Pradesh are interested in Karnataka because they are having power-sharing projects in Karnataka. That is the simple reason why they are not agitating over the problems of Andhra. Till last year, we had drought for four consecutive years in Andhra Pradesh. Last year also, as of 31.12.2004, we had declared about 757 mandals as drought-affected mandals out of a total of 1104. This year, though we have got the rains, they are inadequate. Still, nine districts are facing severe drought. Around 320 mandals are facing drinking water problem.

Sir, I would like to draw the attention of the Government regarding the employment generation activities. The so-called National Food-for-Work Programme is confined to only eight districts of Andhra Pradesh. Earlier, during our regime, during the NDA regime, we used to have the programme in all the 23 districts. We had brought 55 lakh metric tonnes of rice to Andhra Pradesh to help the people and to contain migration. Now, the programme is confined to eight districts; and more particularly, the backward districts of Telangana like Karimnagar, Medak and Adilabad are the sufferers. Although there are half-a-dozen Ministers from Andhra Pradesh in the Union Cabinet, I don't know what they are doing in Delhi. They are not doing anything for the State of Andhra Pradesh. I request the Government of India that this Programme should be implemented throughout the State. It cannot be a pilot programme. It was already tried and tested and proved to be successful. Then, why should there be a pilot programme to the extent of 150 districts in the country? So, I request the Government to see to it that it is extended to the entire State of Andhra Pradesh.

As far as the recent rains are concerned, we had a little rain during the past 10 days, though it is a delayed rain and the dry spell was very long. The total area available for- cultivation in Andhra Pradesh is around 80 lakh hectares. Out of which, in about 41 lakh hectares, now the crops are raised. The rest of the land is fallow. More than half of the area is fallow. For this simple reason, I would once again request the Government of India that the Food for Work Programme should be implemented throughout the State of Andhra Pradesh. As far as livestock are concerned, we don't have adequate stocks of cattle feed. I would request the Government to help the State of Andhra Pradesh in providing assistance in this regard. The Government of Andhra Pradesh has sought about Rs.1200 Crores as relief to the State, apart from 20 lakh metric tonne of grains. So, in view of the

request made by the Government of Andhra Pradesh and in view of the severe drought in the State, I request the Government of India to come to the rescue of Andhra Pradesh. The present Government of Andhra Pradesh is not at all helping the poor people of Andhra Pradesh. As a result, the rate of migration is very high. The reservoirs are empty. I have the latest data of water levels in various reservoirs of Andhra Pradesh, like Srisailam, Jurala, Nagarjunasagar, etc. All these reservoirs are empty. We are at the mercy of Karnataka. If they release some water, we will have the crops raised; otherwise, we have to face the problem of drinking water also.

Sir, on the other hand, we have problem with Maharashtra. Sir, they have started about 11 projects on river Godavari. More particularly, it will affect the district of Adilabad. My good friend, the senior leader, Shri Jairam Ramesh has adopted Adilabad District -- if I remember correctly -- which is the worst affected district by virtue of Babli Project. So, this is a major issue. It will affect the tribal districts of Adilabad, Karimnagar, Warangal and other parts of Telangana region.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Mr. Ravula Chandra Sekar Reddyji, you have only a couple of minutes, if you don't mind.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: I know, Sir, but the problems are plenty.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Of course, they are.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I request the Government of India to see that construction of illegal projects on the Godavari river should be stopped at once. There is this Babli Project and other 11 projects which are contemplated by Maharashtra.

SHRI B.K. HARIPRASAD: I associate myself with you.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Thank you. I request my friends from Maharashtra to associate with me, when I am saying about our conflict with Karnataka. Then, my problem will be solved. Sir, there is less rainfall, which is just more than 20 per cent. Even after the cyclonic effect, the State of Andhra Pradesh is suffering. Hence, I request the Government of India to extend the Food for Work Programme to the entire State, solve the problem of Krishna waters with Karnataka and the highhanded attitude

of Maharashtra. Andhra will flourish only when both these things would be controlled.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, our great nation is consisting of rivers which are full of water, minerals, nature and everything, but still we have been suffering miserably. On the one side, there are heavy floods, cyclones, etc. On the other side, there are droughts. For example, Sir, about 40 million hectares of land is prone to floods. About 8000 kilometre long coastal line has cyclone seasons. Low and medium rain regions constitute 68 per cent of the total area which are vulnerable to periodic droughts. Like this, Sir, on one side, people are suffering because of floods and on the other, because of droughts. I would also like to say on the impact of drought. Drought will have a bearing on the economy. The country will have to sacrifice at least a percentage point of national output, which is roughly 200 billion. There will be a wider fiscal deficit, bigger subsidy bill, higher inflation rate, which is directly proportionate to the scarcities due to drought.

Drought may force the Government to borrow more than the Budget target. This may also push the deficit Budget higher than the Budget Estimates for fiscal deficit of Rs. 1,35,525 Crores, that is, 5.3 per cent of the GDP.

So, like this, on the one side, there is an unbearable impact; on the other side, a number of States, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Rajasthan, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Orissa, and other States too, if you open newspapers, you would see they are hit with floods, and, on the other side, drought. This is going on parallel. According to the Governmental conservative estimates, 348 lakhs of people in 41 ,000 villages in 236 districts in 16 States, last year, were affected by floods and heavy rains. There has been a colossal loss of over 36 lakh hectares and 6,45,575 houses have been damaged. Loss of human lives has been estimated at 1,865, and that of cattle is 11,290. So, this is a known fact as to how the nation is suffering because of these.

We need to solve this problem. It is not the question of debates, lectures and speeches in the Parliament and various other platforms. You must have the determination, dedication, devotion and concentration everywhere without criticising each other. Irrespective of political affiliations we must all be united, in both the Houses, and strengthen the Government and see to it that the problem is solved.

I analyse very briefly. One is long-term policy, second is short-term and the third is avoidance of fighting among the stakeholder States. Long-term policy means, 50 years back, Dr. K.L. Rao, a political leader, actually advised this nation on the inter-linking of rivers from the Himalayas to Kanyakumari or *vice-versa.* Why is it getting delayed? The main reason is you need lakhs of Crores of rupees for it. Therefore, any Government is not able to concentrate really on how to raise funds and the problems are going on. Here, my suggestion is, nothing is impossible. Though we need a few lakh crores of rupees, let us make a small beginning. Let us take the help of the World Bank, the ADB, and other international organisations and in about 20-30 years we must be able to complete. But nothing is happening. This is the real agony.

I again call upon the Government to concentrate on inter-linking of rivers, at least in a small way. Every year, we must provide a good Budget for this and get going.

There is another thing I want to mention. The moment floods come, they say, "It is the responsibility of the State Governments and Centre gives assistance." That is okay. Actually, there is no proper coordination; there is no timely help from Centre to States and fighting with each other. So, let us avoid this confusion. Now, this must be taken up by the State Governments and the Centre in such a way that whenever a calamity takes place, we must take steps immediately.

Even in this House we are seeing. We are all colleagues. I am from Andhra Pradesh. Next, of course, I love Maharashtra and Karnataka. But river water is not being released. We must sit coolly and see to it that whatever water is due must be given by Karnataka, must be given by Maharashtra. Nothing is impossible.

So, I request the Central Government to take the initiative. They must bring both the Governments sit across a table and solve the problem. Of course, there is a perennial problem of the Cauvery. Both Governments may not immediately solve it. But as far as Krishna water is concerned among Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh, I do not think it is impossible. It is possible. It should be solved. Let us not avoid solving it.

One most important thing what we need to do is, instead of simply toying with the ball and fighting with one another, criticising, let us admire anybody who is doing a good job. In Andhra Pradesh, for example, let us not see it politically. In the history of Andhra Pradesh, for the first time, the

present Government has come forward with a determination not to waste water. When heavy rains come, when it floods, it should not go to the sea. It is not the solution. Instead, we must have irrigation projects.

Let us build these projects and see that water is not wasted. Sixty lakh acres should be irrigated. This is the scheme. All must admire that. Don't keep criticising in some way or the other. They are afraid that we will get good name once it is implemented.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: It is very strange. Nobody objected about the construction of projects. We only objected about the swallowing of money in the name of projects.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Regarding money, whenever any Government is productive, is creative, the Central Government will always support. For a temporary name and image, you buy a product for Rs. 5 and give it at Rupee one. That will not solve the problem in the long run. You must spend on productivity. Irrigation projects are rupees invested either by Central Government or by the public bonds or by institutions or by banks or by international institutions. It is going to help the nation, the State and every human being. Therefore, it is a good example. Every State must follow this. Most of the States must follow Andhra Pradesh's example without criticising. This is not hypocrisy. How can they get money? Money will come. India is still rich. There are so many potentialities. We are growing like anything. Today the prosperity is unimaginable in India. We can get it. Therefore, let us not be pessimistic. Let us be optimistic. How will money come? This is not the question. Now, Sir, drought problem will be solved if the projects are constructed so that even if drought is there, the project's water through canals will irrigate. This is very simple solution. Therefore, you must construct projects not only in Andhra Pradesh but also all over India. How? One is through the Centre and the second is through the State. Let the other States admire the States who have got the challenge, courage and determination to come forward to build it. Take for example, Andhra Pradesh. The States also must come. So a day must be seen in India where a number of States must come forward and build projects like Andhra Pradesh and follow the example of Andhra Pradesh without criticising and see that water is not wasted, If water is not wasted, drought, can also be avoided. Thirdly, let us not criticise like children. We are the valuable citizens of the country.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: We will be happy if he settles the issue. We are quarrelling like children. As an elderly man he can settle the issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): May I suggest how all of you can resolve the issue? All of you resolve not to brief any lawyers.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, children mean not merely children. This is an idiomatic language, not dramatic language. I am using the word 'children' in a different concept. Finally, I am concluding. Mr. Chidambaram is there. He must concentrate on the drinking water system in a very gradual way, in a phased manner. Drought and floods is interlinked with Finance Ministry. Whenever droughts and floods come his Budget is affected. His cash flow is affected. It is interlinked. Therefore, we must see that every State starts and in a few years you will find the real prosperity and progress of the nation. Thank you.

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के अनेक हिस्सों में अतिवृष्टि के कारण कुछ स्थानों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई हैं और कुछ स्थानों पर सूखे की स्थिति भी हैं। मैं यहां बाढ़ से संबंधित मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के बारे में अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हूं । जुलाई के प्रथम सप्ताह में जिस प्रकार से एकदम बाढ़ का प्रकोप आया, एक दम अतिवृष्टि हुई, बारिश बहुत हुई , प्रायः शुरुआत में इतनी बाढ़ कभी नहीं आती हैं लेकिन अप्रत्याशित रुप से जिस प्रकार से हैंवी रेन्स हुए, उसके कारण मध्य प्रदेश के नौ जिलों में जुलाई के प्रथम सप्ताह में भयंकर रूप बाढ आयी और अभी कल ही मध्य प्रदेश के छिंदवाडा जिले में दो दिन से निरंतर बारिश के कारण बाढ की स्थिति निर्मित हुई हैं। इस प्रकार सागर- दमोह-पन्ना-सतना सहित अभी तक कुल दस जिले पूरी तरह से बाढ़ से अफैक्टिड हो चुके हैं, 1,355 गांव इससे प्रभावित हुए हैं, 6 शहर प्रभावित हुए हैं और 12 लाख परिवार एक प्रकार से इस बाढ़ के कारण पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 64 व्यक्तियों की मृत्यु नौ ज़िलों में हुई थी, छिन्दवाड़ा ज़िले में उमरिया नाले में बहने के कारण कल तीन और कैज़ुअल्टीज़ हुई हैं। इस प्रकार लगभग 67 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी हैं और 42 हज़ार जानवर इसमें मारे गए हैं। यह जो जितने ट्रेस हो पाए थे, वे हैं , लेकिन इसके अलावा जो बाढ़ में बह गए, उनकी संख्या का कोई अनुमान नहीं हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो बाढ़ के कारण 60,000 मकान तो पूरी तरह से नष्ट हुए हैं और लगभग सवा लाख मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुल मिलाकर करीब डेढ-पौने दो लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। यदि इस सबको देखें, तो आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बाढ़ के कारण कितनी व्यापक रुप से क्षति हुई हैं, जन –हानि हुई हैं, धन-हानि हुई हैं, इसके अलावा पशुओं की भी हानि हुई हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में जैसे ही बाढ़ आई थी, उस समय जो तत्काल प्रारंभिक सर्वे किया गया था, उस समय इसकी क्षति का अनुमान लगभग पांच सौ करोड़ रुपए था। यह आकलन तो इन सारे मकानों के लिए, व्यक्तियों पशुओं आदि की क्षति के आधार पर था। लेकिन जो पुल बगैरह बह गए, जो सड़के नष्ट हो गई, सिंचाई के बांध टूट गए, जो नहरें पूरी तरह से टूट गई, पेयजल की आपूर्ति के साधन नष्ट हो

गए, कुंए टूट गए, ट्यूबवैल्स खत्म हो गए, गांवो और शहरों में लगे हुए बिजली के खम्भे पूरी तरह से उखड़ गए, नष्ट हो गए, कहीं शाला भवन नष्ट हो गए- यदि इन सबका हम अंदाज लगाएं, किसानों का बीज, जो उन्होंने बोया था, वह पूरी तरह नष्ट हो गया, घरों में जो बीज रखा हुआ था, जिसकी बुवाई वे नहीं कर पाए थे, जो खाद और बीज घरों में रखा हुआ था, पानी भर जाने से उसकी क्षति हो गई हैं। इन सबको यदि हम देखते हैं तो उससे सीधा-सीधा हमको लगता हैं कि लगभग 1,000 करोड़ से अधिक की क्षति मध्य प्रदेश के नौ- दस जिलों में हो चुकी हैं। 500 करोड़ के लगभग का तो आकलन भी हुआ हैं और यदि हम हरेक चीज का हिसाब लगाते हैं, तो आज इतनी बडी क्षति मध्य प्रदेश में इस बाढ़ के कारण हुई हैं ।

महोदय, दूसरी सबसे बडी बात यह हैं,हम देख रहे हैं कि लगभग 1,355 गांवों की सीमा में आने वाले यदि सर्वे और जमीन का हिसाब लगाएं , तो सैकड़ों हैंक्टेयर ज़मीन होती हैं, यह सीधा-सीधा आकलन किया जा सकता हैं। यदि इस सबको हम देखते हैं तो जहां बुवाई हो गई थी, वह खेती नष्ट हो गई । अब बाकी के स्थानों पर आज ऐसी स्थिति बन गई हैं कि किसानों के पास खाद, बीज नहीं हैं। बुवाई करने का समय निकल चुका हैं, वे बुवाई नहीं कर सकते हैं और एक प्रकार से, इतने गावों मे किसान खरीफ की फसल नहीं ले पांएगे। यदि वे खरीफ की फसल नहीं लेते हैं, तो इस बार खेत खाली पड़े रहेंगे, जब तक रबी के लिए कोई साधन न जुटा पाएं या उस समय रेन्स न हों, या जिनके पास इरिगेशन का साधन होगा, वे ही कुछ कर पाएंगे, लेकिन तालाब के टूटने से इरिगेशन भी संभव नहीं हैं। कुल मिलाकर एक भयावह दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता हैं। इस सबके बारे में यदि हम , जो हमारी प्रक्रियाएं और नियम हैं, उन्हें देखे, तो जो क्षति हुई हैं, उसके अनुसार मुआवजा होता हैं, लेकिन आज तक न केन्द्र सरकार ने इस प्रकार की कोई नियमावली बनाई हैं, न राज्य सरकारों के नियमों में, उनके जो आर.बी.सी. के रूल्स हैं, उसके अंतर्गत भी इस प्रकार जो खेत खाली रह जाते हैं, किन्ही कारणों से, चाहे बाढ़ के कारण से या अन्य कारणों से, उससे होने वाली क्षति का कोई आकलन ही नहीं करता हैं, इसलिए उनको कोई सहायता ही नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इस सबको देखने से पता चलता हैं कि मध्य प्रदेश में 1,000 करोड़ से अधिक की क्षति हुई हैं। यह मैं केवल इसके आकलन के आधार पर ही नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की सरकार ने बाकायदा यहां केंद्र सरकार को रिमाइंडर्स भेजे हैं, एक के बाद एक प्रतिवेदन भेजे हैं और उसमें उन्होंने हरेक चीज़ का आकलन दिया हैं कि पहले के 64 और कल के 3, जो इसमें मरे हैं, जो इसमें काल-कवलित हुए हैं, यदि उनको पचास हज़ार रुपया भी देते हैं, तो लगभग चालीस- पचास लाख रुपया तो इसी का होता हैं । इसी प्रकार से जो करीब 42,000 कैटल्स मरे हैं, तीन हजार रुपए प्रति कैटल के हिसाब से भी यदि क्षतिपूर्ति देते हैं, तो उसका कितना होगा? इसी प्रकार से जो मकान गिरे हैं, पूरी तरह से जो डैमेज हो गए हैं, उन मकानों को फिर से बनाने के लिए यदि दस हजार रुपया प्रति मकान के हिसाब से भी लगाएं, तो उसके लिए लगभग साठ करोड़ रुपए के आसपास की लागत आती हैं। इस प्रकार से जो मकान थोड़े से डैमेज हुए हैं, यदि उनको हम तीन हजार रुपए क्षतिपूर्ति के आधार पर दें, जिससे वे उनको अपने रहने के लिए फिर से ठीक-ठाक कर पाएं, तो उसके लिए लगभग अन्य तीस करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती हैं। कैश रिलीफ फंड भी देना हैं उसके बाद दवाओं के लिए हैं, फिर उनके लिए अनाज सप्लाई करने का काम हैं और फिर बाकी की सारी चीजों के लिए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सरकार ने 628 करोड़ रुपए का आकलन दिया हैं कि हम किस-किस चीज में सहायता देंगे। इसके लिए उसका कहना हैं कि क्षतिपूर्ति पैसे के माध्यम से या अन्य साधनों से कर रही हैं। इसका पूरा फैक्चुअल और

पूरा एसेसमेंट करके मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया था। इसके अलावा जो बाकी की क्षति हुई हैं, उसके बारे में भी और आकलन करके बाकी की रिपोर्ट भेजी जा रही हैं। 12 वें वित्त आयोग में नेच्युरल कैलामिटीज फंड के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रोविजन हैं कि मध्य प्रदेश को कंरंट ईयर में 225 करोड़ रुपया दिया जाना हैं। माननीय सभापति जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा हैं कि अभी तक केवल 95 करोड़ रुपए की पहली किश्त रिलीज हुई हैं। जबकि मध्य प्रदेश की सरकार अपने पास से लगभग 100 करोड़ रुपए के आस-पास, इन सारी चीजों के जुटाने में और अन्य व्यवस्थाओं में, अपने पास से खर्च कर चुकी थी। अभी तक केवल 95 करोड़ रुपया ही रिलीज हुआ हैं। यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी हैं, यदि इसकी दूसरी किश्त भी तत्काल दी जाए तो वहां पर रिलीफ दिया जा सकता हैं। लेकिन , मैं सोचता हूं कि यदि हम केवल इतने पर ही रुक जाएंगे कि 225 करोड़ रुपया आए तो , मैंने सारा आकलन आपके सामने रखा हैं, एक –एक चीज का आकलन हैं, उसके आधार पर केवल यदि यही कि हम 254 करोड़ रुपया नेच्युरल कैलामिटीज के लिए देने वाले हैं, आप इससे मीट आउट करें तो मैं सोचता हूं कि यह मध्य प्रदेश के साथ अन्याय होगा। मैं आज ही समाचारपत्रों में पढ़ रहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विशेष पैकेज के अंतर्गत 100 रुपया दिया है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं, लेकिन अन्य स्टेटों के साथ भी इस प्रकर उदार दिल से, आवश्यकता के हिसाब से , उनकी जरुरत के हिसाब से देने के बारें में भी विचार करना चाहिए। अब जो वहां स्थिति बनी हुई हैं .....(व्यवधान).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S, NARIMAN): Will you please finish in two minutes?

श्री विक्रम वर्मा: ओ.के. महोदय, जो वहां पर स्थिति बनी हुई हैं, बाढ़ प्रभावित जिलों में 13 लाख परिवार तो BPL के हैं। यह आलरेडी सर्वे किया हुआ हैं कि 13 लाख BPL के रहने वाले परिवार हैं। आज इन परिवारों के पास अनाज नहीं हैं, बाढ़ के कारण उनके पास करने को मजदूरी नहीं हैं। किसान का खेत समाप्त हो जाने से जो एग्रिक्लचरल लेबर हैं, वह भी बैठा हुआ हैं, क्योंकि खेतों में बुवाई नहीं हुई हैं, खेतों में काम नहीं हैं। ये जो 13 लाख BPL परिवार हैं, इनके लिए तो जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा हैं। रहने के लिए उनके पास छत तक तो हैं नहीं, इसलिए इन सब को अनाज देकर मदद करनी पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं। जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनको मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से 30 किलो अनाज तत्काल दिया हैं। यह भी निर्णय किया हैं कि सरकार इन परिवारों को तीन महीने तक खाद्यान्न अपनी तरफ से देगी। लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं, इतने लाख परिवारों को वह कितने दिन तक अपने पास से दे सकती हैं? इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध हैं कि वह अधिक से अधिक खाद्यान्न का अतिरिक्त कोटा दे। इस तरह से 13 लाख तो सीधे-सीधे ये परिवार हैं और जो APL इनके ऊपर वाले हैं, उन किसानों के पास भी कुछ नहीं बचा हैं, उनके लिए भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तत्काल अतिरिक्त खाद्यान्न देने की आवश्यकता हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने यद्यपि तत्काल यह कोशिश की और माननीय मुख्य मंत्री जी गए, माननीय मंत्री जी गए, अधिकारीगण गए और उन्होंने वहां जाकर राज्य सरकार की तरफ से यथासंभव प्रयास किया हैं। उन्होंने परिवारों के लिए अस्थाई रूप से छत बनाने का निर्णय भी किया हैं। उनके लिए पॉलिथीन, बांस, बल्ली और लकडियां बांटने का काम प्रारंभ किया हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की हैं। वहां पर कैम्पस भी

लगाए हैं। जो 42 हजार मरे हुए पशु गांव और खेतों में पड़े थे, यदि उनको तत्काल नहीं दफनाया जाता तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि इससे एक महामारी फैल सकती थी। महोदय, सबसे बडी प्रोब्लम यह आ रही हैं कि इस बाढ़ के कारण कुंए धंस गए, ट्यूबवैल्स खत्म हो गए, जिसके कारण वहां पर पीने के पानी की दिक्कत आ रही हैं। तत्काल पेय जल की व्यवस्था करवाने के लिए नए सिरे से टयूबवैल की व्यवस्था करवाएं, जो कुछ जगह पर पाइप लाइन्स टूट गई हैं, उनको ठीक करवाना हैं तो उसके लिए लगभग 40-50 करोड़ रुपए का एसेंसमेंट इमिडिट मध्य प्रदेश सरकार ने किया हैं। इसके लिए इतना पैसा लगेगा नहीं तो कल लोगों को शुद्ध पेय जल नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार यह जो सारी स्थिति हैं, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अपने लेवल पर इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि राज्य सरकारों की एक सीमा होती हैं। इसलिए इस सारे एसेंसमेंट के आधार पर, अभी तक जो रिलीफ मिला हैं, हमारे अधिकार के पैसे में से 12 वें वित्त आयोग से एक मात्र किश्त मिली हैं। बाकी का कोई पैसा अभी तक नहीं मिल पाया हैं। यहां पर माननीय कृषि जी यहां पर बैठे हुए हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध हैं कि वे नेच्युरल कैलामिटीज को देखते दुए, अभी यहां पर वित्त मंत्री जी भी थे, यदि अधिक से अधिक मध्य प्रदेश को देंगे तो जो दस जिले प्रभावित हुए हैं, और इतने लाख जनसंख्या जो मैने बताई हैं, उसके लिए यह सब हो पाएगा। आने वाली रबी की फसल के बारे में हमें चिंता करनी पड़ेगी, अन्यथा यह पूरा साल उसके बिना हो जाएगा। इसलिए इन सबके साथ मेरा निवेदन हैं कि मध्य प्रदेश के लिए विशेष पैकेज देते हुए, विशेष राहत, जो 245 करोड़ बनती हैं, केवल उससे काम नहीं चलेगा, इसके अतिरिक्त भी धनराशि देने का कष्ट करेंगे तो निश्चित रुप से हम ऐसे कष्ट के समय में जनता के साथ खड़े होकर उनके दुख को बांटने में समर्थ हो सकेंगे। इन्ही शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री विद्या सागर निषाद (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, आज सुखाड़ और बाढ़ पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह पंरपरा से होते हुए आया हैं कि जब सुखाड़ का टाइम आया , जब बाढ़ का टाइम आया तो हम लोग उस ओर मुखातिब होते हैं, लेकिन मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार में जो बाढ़ का तूफान आता हैं, वह बिहार का पानी नहीं होता, बिहार की वर्षा का पानी नहीं होता और न ही पहाड़ का पानी होता हैं। अगर किसी राज्य में विदेशियों का हमला होता हैं तो उसका मुकाबला करने के लिए केन्द को ही मुखातिब होना पड़ता हैं । हमारे बिहार के अंदर विदेशी हमला होता हैं। नेपाल से पानी आने की वजह से आज हम काफी बर्बाद हैं। अगर वहां पर हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होता, आज से नहीं, बल्कि पंरपरा से ऐसा देखा गया हैं कि नेपाल का पानी आते हुए भी, आज तक उस ओर बिहार की ओर मुखातिब नहीं होने की वजह से बिहार से बहुत गरीबी हैं। अभी-अभी चर्चाएं हुई कि मजदूर कहां का मारा गया। बिहार का, कारखाने में काम करने वाला मजदूर मारा गया। क्या कारण हैं? एक ही कारण हैं। हमारे सामने गरीबी हैं। हमारे पास ऐसी जमीन हैं, जिस जमीन के माध्यम से हम काफी पैदावार कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी जमीन हैं, जिस जमीन के माध्यम से हम काफी पैदावार कर सकते हैं। हमारे यहां एक हेक्टेयर जमीन पर, एक बीघे जमीन में मिनिमम चालीस क्विंटल मकई पैदा करते हैं। लहलहाता हुआ पौधा होता हैं, लेकिन नेपाल का पानी, बाढ़ का पानी आया और सारी फसल नष्ट हो जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गत वर्ष भी हाउस में जब चर्चाएं हुई थी, तब उस समय भी इस बात की चर्चा आई थी कि नेपाल के साथ हम बात कर रहे हैं। अगर नेपाल के साथ बात करने के बाद वहां पानी का टैंक बनाया जाए, वह पानी के टैंक के रुप में बन जाता हैं तो इससे एक फायदा नहीं, बल्कि अनेकों फायदे, बिहारवासियों को ही नहीं , बल्कि अनेकों राज्यों को होंगे। हम इससे

बिजली पैदा कर सकते हैं, हम फिशरीज, मछली का उत्पादन कर सकते हैं, इरीगेशन, खेती सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन हम उस ओर मुखातिब नही होते। बाढ़ आती हैं तो रिलीफ दिया जाता हैं। रिलीफ कौन खाते हैं? जो निहायत गरीब, जिसके पास कुछ शाक्ति नहीं हैं, उसे भिखमंगा बनाकर रिलीफ के रूप में दिया जाता हैं। जितने पैसें हमें दिए गए हैं, जब भी दिए गए हैं, उसकी जगह अगर सिर्फ एक ओर मुखातिब होते कि हम उस बाढ़ के पानी को कैसे रोकें तो अच्छा होता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा भारत सरकार से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसका कोई उपाय हो। बिहार में आज से नहीं, बल्कि बहुत दिनों से बहुत से तटबंध हैं। तो तटबंध बांधे गए थे, हमारे राज्य के अंदर जितनी नदियां हैं, गंगा, कोसी, बागमती, कमला, काली कोसी, बालन आदि, ये सारी नादियां बिहार के अंदर खगडिया जिले में जाकर विलीन हो जाती हैं। परिणाम होता हैं काफी बाढ़ होने की वजह से तबाही । माननीय प्रधान मंत्री जी हाउस में थे, मैंने उस समय भी उन्हें इस ओर मुखातिब किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने वहां हवाई जहाज के द्वारा सर्वेक्षण किया था, उन्होंने सारा दृश्य देखा था। बाढ़ आने के बाद जो फूस का मकान बना रहता हैं, उस पर मनुष्य बैठ जाते हैं। उस पर सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि सांप, बिच्छू सभी विराजमान रहते हैं। अब सोचा जा सकता हैं कि बिहार के साथ क्या जुल्म होता हैं? मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे तटबंध हैं, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, जैसे गोगरी से नारायणपुर, नारायणपुर से बदला, बदला से समस्तीपुर । ऐसे करीब दस –ग्यारह जिले हैं, जहां 1952-53 में तटबंध बने हैं और उसके बाद आज तक उसकी मरम्मत का काम ही नहीं हुआ हैं। मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि यह राज्य सरकार की क्षमता के बाहर की बात हैं और जब तक केन्द्र सरकार उस ओर मुखातिब नहीं होगी, केन्द्र सरकार उस ओर देखने का काम नहीं करेगी, यह काम नहीं हो सकता ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिहार राज्य को खंडित किया गया, उसका एक ही करण था कि वहां की सरकार को गिराने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा एक साजिश रची गई थी। बिहार को दो टुकड़ो में बांट दिया गया , एक तो झारखंड बन गया और दूसरा बिहार हुआ। हमारी जो सोर्स आफ इंकम थीं, जो हमारी आमदनी के स्त्रोत थे, वे सारे के सारे झारखंड में चले गए और बिहार के पास क्या बचा? बिहार के पास 33 फीसदी , यानी 100 रुपए में 33 रुपए रह गए, जहां की आबादी 8 करोड़ की हैं और बाकी की आमदनी 2 करोड़ की आबादी के लिए चली गई । इस तरह सारे पैसे के स्त्रोत उधर चले गए। उस समय कहा गया था कि बिहार के साथ बहुत सी मुसीबतें हैं, उसके लिए हम विशेष पैकेज देंगे, भारत सरकार के जो पूर्व प्रधान मंत्री थे, उन्होंने यह पैकेज की बात की थी और उससे मुझे आशा लगी थी कि अब बिहारियों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क हुआ। एक भी पैसे का पैकेज मुझे नहीं दिया गया, जिससे हमारी बर्बादी हैं। इसलिए मैं अपनी भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पैकेज देने की बात पहली सरकार ने की थी, आप उस ओर मुखातिब होकर जो हमारी बर्बादी हैं, उसे बचाने का काम करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां दूध का उत्पादन होता हैं, हमारे यहां मछली का उत्पादन होता हैं, हमारे यहां कृषि का उत्पादन होता हैं, हमारे यहां इन सारी चीजों का उत्पादन होता हैं, लेकिन हम उस ओर मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस ओर भारत सरकार की ओर से उपाय किए जाने चाहिए। वहाँ बाढ़ फिर से आ रही हैं, बल्कि बाढ़ आ गई हैं और बाढ आने के बाद क्या स्थिति होगी, यह कहना

मुश्किल हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार बिहार की ओर मुखातिब हो । अगर बिहार में इंसान हैं, तो इंसानियत की हैंसियत से हम लोगों को कुछ राहत देने का काम आप करें, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। हमारे जितने भी कल- कारखाने थे, जितनी भी हमारी मजदूरी की स्कीमें थी, वे सारी की सारी झारखंड में चली गई । आप देखिए, आज बिहार का मजदूर कहां जाता हैं? सारे देश के पैमाने पर रिक्शा चलाने वाला कहां का हैं? वह बिहार का हैं, बिहारी हैं। मजदूरी करने वाला कहां का हैं? बिहारी हैं। चाहे मुम्बई में हो , कलकत्ता में हो, असम में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, या एशिया के अन्य देशों के अगल-बगल के राज्यों में मजदूरी करने वाला बिहारी होता हैं। इसका कारण एक ही हैं और वह हैं नेपाली हमले की वजह । अगर बिहार में बाढ़ को रोका जाए, पानी का वहां स्त्रोत बना दिया जाए, तो बिहार के पास इतनी क्षमता होगी कि हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं। यह जानबूझ कर हम लोगों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया गया और इसी का परिणाम हैं कि आज बिहार गरीबी से बहुत नीचे हैं। मैं आग्रह और निवेदन के साथ यह चाहता हूँ कि जिस बिन्दु पर मैंने अपनी बात रखी हैं, माननीय सरकार उस ओर मुखातिब हो। इतना कहकर आपने जो मुझे मौका दिया हैं, इसके लिए धन्यवाद । नमस्कार।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Shri Pyarimohan Mohapatra. He is not here. Shri R. Shunmugasundaram, you have five minutes.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Mr. Vice-Chairman, Sir, we have been experiencing floods on the one side and drought on the other side, in our country. We have been discussing about this problem for a very long time. Fifty-five years after Independence, these two situations are being discussed. There is a lot of planning that has undergone to remedy the situation. Sir, when the UPA Government was formed, it assured various things in this regard through the Common Minimum Programme. Regarding Agriculture, it said, "The UPA Government will introduce a special programme for dryland farming in the arid and semi-arid regions of the country. Watershed and wasteland development programmes will be taken up on a massive scale. Water management in all its aspects, both for irrigation and drinking purposes, will receive urgent attention." Likewise, while dealing with water resources, the UPA Government in its Common Minimum Programme has said, "The UPA Government will make a comprehensive assessment of the feasibility of linking the rivers of the country starting with the southbound rivers. This assessment will be done in a fully consultative manner. It will also explore the feasibility of linking sub-basins of rivers in States like Bihar. The UPA will take all steps to ensure that long-pending inter-State disputes on rivers and water-sharing like the Cauvery Waters dispute are settled amicably at the earliest keeping in mind the interests of all parties to the dispute." It further said, "To put an

end to the acute drinking water Shortage in cities, especially, in Southern States, desalination plants will be installed all along the Coromandel Coast starting with Chennai. Special problems of habitations in hilly terrains will be addressed immediately."

Sir, these were the promises which were made by the UPA Government. But, what is the present situation in Tamil Nadu? I have to highlight what is happening presently in Tamil Nadu. What is happening is that the six delta districts in Tamil Nadu, which are called the rice bowls of the country, which are producing rice not only for the whole of Tamil Nadu but for some portions of Kerala also are suffering without water. This is a crucial time. The *kharif* crop has to be cultivated at this moment. The interim award which has been given by the Tribunal for this season, especially, for June, July and August is 107 TMC, but what is flowing from Cauvery, at present, is only 0.6 TMC of water. That is also not the water that is being released by any Government, but that is the water which is over-flowing in the Kabini and other rivers because of the rains in the catchment area. Therefore,, Sir, there was a representation of the UPA constituents of Tamil Nadu led* by the former Minister of Tamil Nadu and the present Leader of the Opposition, Prof. K. Anbazhagan. All the Members of Parliament of the UPA from Tamil Nadu met the hon. Prime Minister and demanded the release of water at this crucial juncture, otherwise, the crops will fail and there won't be any purpose of making water available at a later stage. This is the situation. If water is not released from the Cauvery and no water is allowed for the *kharif* crop at the moment, the youths of Tanjore and other delta areas would migrate to other districts or even to other States for seeking jobs as agricultural labourers or they would go abroad to places like Malaysia and Singapore to undertake hard labour. Sir, this is the situation and it should be immediately prevented. In the last Budget, the hon. Finance Minister has made an assurance for providing funds for deepening, desilting, and preserving the water bodies. I do not know what is being done in this regard. ! request that the Government should come forward and inform this House as to what is happening on that particular front. Likewise, I read about the desaiination plant also. The hon. Finance Minister, in. the last Budget, had announced that Rs. 1000 crore would be set aside for the desalination plant that would come up on the Coromandel Coast and that the first plant would be established at Chennai. Nothing is being done till today.

4.00 P.M.

Sir, drought is man-made, because the level of ground water is depleting... (*Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Is the State Government cooperating or not?

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: The Finance Minister has gone
on record saying that the State Government is not cooperating, but that is not an issue now...*(Interruptions)* .... That is not an issue now.

SHRI P.G. NARAYANAN: Simply announcing the plant is not enough. You need to release the money as well....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Please, let us not have this crossfire. Please, continue.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, the groundwater is depleting because there is no proper rainwater conservation project. That is the situation that we are facing. At this juncture, I thank the hon. Member, Shri Narayanasamy. Though he is from Pondicherry, his State would also be benefited because Pondicherry is also situated on the Coromandel Coast. At least, the first plant at Chennai should come up.

Sir, we have been receiving average monsoon during the last five years. But still, there is no proper storage; that is the situation. Therefore, Sir, through you, I urge upon the Government to tell this hon. House as to what has happened to the projects, the assurances they have given, and the subsequent announcements made in the Budget, the budgetary allocations, and what is happening in regard to the plants they have announced so far.

With these words, I thank you, Sir.

प्रो0 अलका क्षत्रिय (गुजरात): धन्यवाद महोदय, आज देश में बडी गंभीर समस्या हैं। देश के कुछ राज्यों में सूखा पड़ा हैं तो कुछ राज्यों में बाढ आई हैं। इतना ही नहीं देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उसी राज्य के कुछ भागों में सूखा पड़ा हैं और कुछ भागों में बाढ़ आई हैं। सरकार को इन स्थितियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे । कुछ राज्यों में तो हर साल बाढ़ आती हैं या हर साल सूखा पड़ता हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि प्लानिंग कमिशन को इस बात को ध्यान में रख कर एन्यूअल एलोकेशन ऑफ फंड देना चाहिए, पापुलेशन के साथ –साथ ये बाते भी ध्यान में रखनी चाहिए।

महोदय, अब मैं अपने प्रान्त गुजरात के बारे में बात करूंगी। पिछले कुछ सालों से गुजरात में प्लेग, साइक्लोन, गोधरा कांड व उसके बाद हुए दंगे, सूखा व बाढ़ जैसी कुदरती एवं मानव सृजित आपदाओं के कारण बहुत भारी नुकसान हुआ हैं। काफी लोगों ने तो अपनी जानें तक गंवाई हैं। इस साल मानसून के फर्स्ट राउंड में जून –जुलाई महीने में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण गुजरात में काफी नुकसान हुआ हैं। राज्य के कुल 25 में से 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उनमें से भी बडोदरा, आंणद एवं खेड़ा जिले बुरी तरह से असर ग्रस्त हुए हैं। बाढ़ प्रभावित ज़िलों में केवल एक हफ्ते में सीज़न की करीब 84% बारिश हुई थी। पिछले करीब सौ सालों में इतने कम समय में इतनी भारी बारिश कभी नहीं हुई हैं। बाढ़ की वजह से 80 ब्लॉकों के कारीब 10,000 गांवों में नुकसान हुआ हैं। राज्य का 65% भौगोलिक विस्तार प्रभावित हुआ हैं। राज्य की कई नदियों में बाढ़ आई हैं। विश्वमित्री वात्रक, सेढी जैसी नदियों में थोड़े से समय में पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा था। बाढ़ की वजह से 213 लोगों की मौत हुई हैं, 3 लाख से ज्यादा प्रभावित लोगों को वडोदरा, भरूच, खेड़ा, आंणद, सूरत और नवसारी जिलों में सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना पड़ा था। अकेले वडोदरा जिले में ही एक लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब सात हजार से ज्यादा पशुओं की मौत हुई हैं ।

भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कुल 6,719 गांवो में बिजली की आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ा हैं। 5,752 गांव में पीने के पानी की योजनाओं पर बाढ़ का असर पड़ा हैं। अहमादाबाद –बडोदरा एक्सप्रेस हाइवे, नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे और 1561 पंचायतों की करीब 20,000 किलो मीटर रोड और 6000 क्रास ड्रेनेज वर्क्स असरग्रस्त हुए हैं। रेलवे ट्रेक पर पानी आ जाने से काफी ट्रेन सेवाएं रद्द करनी पडी थीं, जिससे हजारों यात्रियों को रेलवे प्लेट फार्म पर आसरा लेना पड़ा था। भारी बारिश की वजह से काफी गांव, देश और दुनिया से अलग थलग पड़ गए थे। लैंड लाइन फोन, सेल फोन या रोड , ट्रेन , मीडिया , टेलीविजन, रेडियों, न्यूजपेपर से वहां का कोई सम्पर्क नहीं हो रहा था। लोगों को बचाने के लिए आर्मी और पैरा मिलट्री फोर्स की मदद लेनी पडी थी। बाढ की गंभीर स्थिति को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने 500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज घोषित किया हैं। इतना ही नहीं 4 जुलाई को 92.25 करोड़ रुपए का कैलेमिटी रिलीफ फंड राज्य सरकार को दिया हैं। बाढ की आपत्ति आने के बाद गुजरात के प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए गए हैं, पर मुश्किलें समाप्त नहीं हुई हैं। इसके लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन योजना और उसके कार्यान्वयन को प्राथमिकता देनी होगी। सबसे मुख्य समस्या आवास की हैं। काफी लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। केन्द्र सरकार ने गुजरात को जो धन उपलब्ध कराया हैं उसमें से युद्ध स्तर पर मकान निर्माण का कार्य शुरु करना होगा, जिससे विस्थापित लोग वापस अपने घरों में जा सकें । बाढ़ के कारण खाद्य आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रभावित लोगों को एक सुदृढ़ वितरण व्यवस्था के माध्यम से जीवनोपयोगी चीजें पहुंचानी होंगी। बाढ़ के बाद महामारी फैलने की संभावना हैं। मुझे पूरी उम्मीद हैं कि राज्य सरकार की तरफ से समुचित कार्रवाई की जा रही हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं और गुजरात की जनसेवा की भावना रखने वाली प्रजा ने इस विपदा का हिम्मत से सामना किया हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। विपत्ति के समय में माननीय रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने भी गुजरात का दौरा किया था।

मध्य और दक्षिण गुजरात में बाढ़ की वजह से फसल को भारी नुकसान हुआ हैं। मेरा केन्द्र और राज्य सरकार से निवेदन हैं कि किसानों को सरल कृषि ऋण देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। कृषि बीमा के अन्तर्गत जो मदद दी जा सकती हैं, उसे भी दिया जाए। वर्तमान में नुकसान हुई फसल के लिए जो ऋण किसानों ने लिया था उसे माफ करने पर विचार किया जाए। और जल्द से जल्द किसानों को बुवाई के लिए मुफ्त बीज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इंडस्ट्रीज सैक्टर में केपिटल लॉस और प्रोडक्शन लॉस हुआ हैं. भारी बारिश और रॉ मेटीरियल नहीं पहुंच पाने की वजह से काफी इंडस्ट्रीज यूनिट बन्द करने पड़े थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और यू0पी0ए0 की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी बाढ़ से प्रभावित वडोदरा शहर का दौरा किया और राज्य सरकार से बाढ़ से प्रभावित लोगों को ज्यादा आर्थिक मदद देने की अपील की हैं।

राज्य में हुई भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारी के नेतृत्व में अलग-अलग मंत्रालयों के 13 प्रतिनिधियों की एक केन्द्रीय टीम ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके क्षति का मूल्यांक्न किया हैं। गुजरात सरकार ने अपने प्रस्ताव में इमरजेंसी रिलीफ, आवास, आरोग्य, खाद्य आपूर्ति, जल आपूर्ति, कृषि और शहरी विकास इत्यादि के लिए 8110 करोड़ रुपयों की मांग की हैं। बाढ़ के साथ-साथ गुजरात के कुछ जिले सूखाग्रस्त हैं, यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अधिक से अधिक धन राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जिससे बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकें और जनजीवन जल्द से जल्द सामान्य हो सकें।

डा0 नारायण सिंह मानकलाव (नाम –निर्देशित): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, काफी देर से सूखा और बाढ़ पर माननीय सदस्यगण चिंता व्यक्त करते आ रहे हैं। यह एक ऐसी परम्परा सी बन गई हैं कि हर साल बाढ़ आती हैं, हर साल सूखा पड़ता हैं और हर साल हम यहां पर चर्चाएं करते हैं।। आजादी से पुर्व भारत कई रियासतों में विभक्त था और उसके चलते कोई सार्वभौमिक परियोजना बना करके इन समस्याओं का समाधान सभ्भव नहीं था। परन्तु आजादी के बाद सम्पूर्ण भारत एक सार्वभौतिक राष्ट्र हैं और उसके लिए इस प्रकार की सारी समस्यों के समाधान हेतु कोई दीर्घकालीन योजना बनाकर उसका समाधान ढूंढने की बात होनी चाहिए जो अब तक नहीं हो पाई हैं। और हम हर साल एक औपचारिकता के रुप में कार्यवाही का संचालने करते हैं और इस प्रकार की चिंता जाहिर करते हैं। समाधान के लिए विचार करते हैं, हम अपनी मांगे रखते हैं और चर्चाएं करते हैं और नतीजा फिर अगले साल वही कहर हम पर पड़ता हैं। इसके चलते संसद और सरकार की कार्यवाही और उनकी जो उपयोगिता हैं, वह प्रश्नवाचक घेरे में आ जाती हैं। इसलिए मेरा सुझाव हैं कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोई ऐसी दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए जिससे इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए हम कोई स्थाई हल निकाल सकें । बाढ़ की बात बहुत हुई हैं, सूखे की बात बहुत हुई हैं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां सूखा स्थाई रुप से निवास करता हैं। राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के "थार" का जो भू-भाग हैं, वह राजस्थान का 60 परसेंट क्षेत्रफल हैं और उसके अंदर हर वक्त, हर साल और इस साल भी जबकि इतनी अतिवृष्टि हुई हैं, वहां अनावृष्टि का प्रकोप हैं और उसके चलते सूखे का बहुत कुप्रभाव वहां की परिस्थितियों

पर- पड़ रहा हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनावृष्टि यहां की नीति बन गई हैं और उसके चलते किसी कवि ने राजस्थानी में लिखा हैं,

"पग पूंगल, धड़ कोटडे, बाहू बाड़मेर।
डिगतो ठिगतों बीकपुर, ठावों जैसलमेर ।।"

कहने का अर्थ यह हैं कि इस पश्चिमी भू-भाग में निश्चि तौर से निंरतर रूप में निवास करने वाला अकाल और कहीं जाता ही नहीं हैं, घूम फिर के वापिस इसी "थार" के रेगिस्तान में आता हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 1992 से 2004 तक केवल इन 11 वर्षो में ही अच्छी वर्षा हुई हैं, बाकी सारे वर्ष अकाल की चपेट में रहे हैं और उसके चलते राजस्थान का विकास पूर्णरूप से बाधित रहा हैं। आज भी 17 जिले अनावृष्टि के शिकार हैं और इसके कारण जो सरकार हमैं फेलनी पड़ती है उनका आंकलन करने के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं । अकाल में तीन तरह के संकट होते हैं- अन्न काल होता हैं, जल काल होता हैं और तृण काल होता हैं, ये तीन काल मिलकर के त्रिकाल बनता हैं और यह त्रिकाल राजस्थान में हर साल बनता हैं, दूसरी जगह कभी-कभी बनता हैं। अकाल में सूखा प्रबंधन के लिए हम काफी खर्चा करते आ रहे हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बाढ़ और अकाल के प्रबंधन के लिए जितना खर्चा हमने पिछले 55 सालों में किया हैं, अगर उस सारे को मिलाया जाए, तो एक अलग भारत बन सकता हैं। इतना खर्चा हमने इस पर किया हैं। फिर भी, यह समस्या हमारे सामने मुंह बाएं ज्यों की त्यों खडी हैं। अकाल के प्रबधंन में कुछ त्रुटियां रहती हैं, उसमें रोजगार की जरूरत रहती हैं, पशुओं के लिए चारे की जरूरत रहती हैं। पीने के पानी की जरुरत रहती हैं और इन तीनों से मिलकर त्रिकाल बनता हैं। अन्न काल, जल, काल और तृण काल, इन तीनों की पूर्ति के लिए उसको काम में लेना पड़ता हैं। राहत कार्य अस्थाई होते हैं जिससे उत्पादकता का कोई प्रश्न नहीं उठता और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचार इसमें लिप्त हैं, उसके कारण गरीब और जरुरतमंद लोगों को रोजगार मुहैंया नहीं होता हैं और सक्षम लोग इसका लाभ उठा लेते हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल इसका एक समाधान हो सकता हैं, अगर सही अर्थों में इसका उपयोग किया जाये, प्रयोग किया जाये, क्रियान्वयन किया जाये। सूखे के कारण विभिन्न प्रदेशों में मौतें होती हैं, किसानों द्वारा आत्महत्याएं होती हैं और कुछ लोगो इसको राजनीति की भट्टियों पर रोटियों की तरह सेंक करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। दूसरा पहलू पीने के पानी का है। आज राजस्थान में जिन जिलों में अनावृष्टि का प्रकोप है, वहां पीने के पानी के लिए लोगों को कई –कई किलोमीटर तक जाना पड़ता हैं। मनुष्य के लिए पानी लाना संभव हैं, परन्तु पशु-धन के लिए इतनी दूरी से पानी लाना बड़ा ही मुश्किल हैं। हमें गांव में बरसात के पानी को रोकने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए एक दीर्घकालीन योजना बनायी जानी चाहिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कई गांवों में टेंकरों से और कई शहरों में रेलों से पानी पहुंचाया जाता हैं। पाली जैसा शहर, जिसमें पांच से दस लाख की जनंसख्या हैं, उसको पूरे 6 महीने तक रेल के माध्यम से पानी की पूर्ति की गयी। आप कल्पना कीजिए कि एक रेल में कितना पानी जाता होगा और किस प्रकार से वहां की आबादी उसक उपयोग करती होगी। जल संरक्षण के कार्य को भी, परम्परागत स्त्रोतों को सुधार कर उसमें उपयोग किया जा सकता हैं और

उसमें वाटर शैड प्रोग्राम प्रभावी रुप ले सकता हैं जिसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भूमि जल का स्तर भी लगातार नीचे होता जा रहा हैं और उसके कारण एक बहुत ही बड़ा संकट पानी का खड़ा होने वाला हैं, ड्रॉट का खड़ा होने वाला हैं

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Will you be able to finish it in a couple of minutes?

डा. नारायण सिंह मानकलावः तीसरा तृणकाल हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हैं, वह हैं हमारा पशुधन। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का 11 परसेंट पशुधन राजस्थान में हैं और राजस्थान के आर्थिक ताने-बाने का 19 प्रतिशत जो हिस्सा हैं, अर्थव्यवस्था का, वह पशुधन पर आधारित हैं और वह पशुधन , जब तृण नहीं होता हैं तो बडी दूभर स्थिति में पहुंच जाता हैं। महोदय, अकाल में एक परिवार को चलाने के लिए 30,40 या 50 किलो गेंहू बहुत होता हैं लेकिन एक जानवर को पालने के लिए, जो चार रुपए या पांच रुपए किलो मिलता हैं। उसमें एक जानवर को पालना परिवार को पालने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता हैं। इसलिए इसके लिए भारत सरकार को फास्टर लैड डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरु करना चाहिए और चारे की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पशुधन बच सकें। अंत में मैं इसकी दीर्घकालीन योजना के तहत पुरजोर शब्दों में यह मांग करूंगा कि राजस्थान जैसे प्रदेश को सूखे से बचाने के लिए रिवर लिंकिंग की जो योजना हैं, जिसके बारें में हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा हैं, मैं फिर एक बार इसकी ओर आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रिवर लिंकिंग प्रोग्राम जब तक नहीं बनेगा, राजस्थान में ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा हैं, वर्षा हो नहीं रही हैं और बिना वर्षा के, बिना पानी के कैसे जी पाएंगे? पैसे से नहीं जीवित रहा जा सकता, चाहे आप कितना ही पैसा दे दें, पैसा जीने का आधार नहीं हैं। जीने का आधार पानी हैं और इसके लिए यह जरुरी हैं कि आप रिवर लिंकिंग स्टार्ट करें और जो भी स्थायी हल हो सकते हैं, अपने प्लानिंग कमीशन के माध्यम से , अपने सोर्सिज़ के माध्यम से, उन उन पर विचार करके ऐसी व्यवस्था करें कि इसका दीर्घकालिक हल निकाला जा सके। धन्यवाद।

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. Let me begin with congratulating the Government for acting in the manner it did when the Tsunami disaster had hit the nation. Thereafter, with all the seriousness, the Government had taken up the issue and formed the Disaster Management Authority. That shows how serious was the Government to tackle this kind of calamities. Having said this, let me come to my State of Kerala, about which I will raise only two-three issues and draw the attention of the Minister. He also knows this very well. One of our major problems is the sea erosion, which is not considered to be **a** natural calamity. Sea erosion is taking away land every time. People and fishermen staying there are suffering. Their houses are washed away; everything is washed away. Unfortunately, Sir, Mr. Sharad Pawar, my friend, also repeated the same sentence as all the other Ministers, "Sorry, this is not a part of natural calamity". So, my first request is, review the whole thing and ensure that Kerala is protected from sea erosion, and also

see what assistance can be extended to the State of Kerala. Secondly, Sir, even yesterday, there was a big landslide in Kerala. Landslide is a big problem. In hilly areas, people are washed away. It affects cash crops and creates a lot of problems for the farmers. Fortunately, Sir, we are a land of cash crops. Paddy cultivation is very limited. There is no wheat cultivation. But, we have cash crops. These cash crops are, as the hon. Minister knows, one of the most important agricultural activities, or, I should say, the backbone of our economy. It is also suffering. We are not getting enough support from the Government. I am not blaming the Government. They always look at paddy, wheat and sugarcane. So far as sugarcane is concerned, it is understandable. ...*(Interruptions)*.... That we are importing. I don't mind that. We are importing more than 50 per cent. These are the major problems which we are facing. Under the present system, we give Plan money to every State. But this is a new system which we have introduced. When you review the whole thing, kindly consider the problem of sea erosion in Kerala which is a calamity for the State of Kerala. Thank you.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, today's debate, of course, is on flood and drought, but I wish to utilise this opportunity to raise an issue which I don't think has ever been discussed in this House and which is, more or less, exclusive to the State of West Bengal, unless it is there to a certain extent in Bihar and perhaps in Assam and, that is, the problem of river erosion. In north Bengal and parts of South Bengal, the Ganga, the Padda, *i.e.* the Padma, as we call it, which goes into Bangladesh and Farakka onwards, is on a rampage. This morning, we were discussing the incident occurred at Gurgaon about which the visual media was repeatedly showing us scenes after scenes of Gurgaon. Well, if you are in Kolkata, and if you are listening to the vernacular visual media, similarly you can see scenes of devastation of erosion particularly in the districts of Malda and Murshidabad over a stretch of about 150 kilometres. Vast chunks of lands are disappearing into the river and the irony of the whole thing is, whereas the Padda, the Ganga, the Mahananda are eating into India, along the West Bengal stretch, it is coming up on the Bangladesh side. The river is changing course. We are losing land and Bangladesh is getting land. The border is changing. Also, due to the erosion of the river at the confluence of the Mahananda, the Ganga, the Bhagirathi, a stage is soon coming when the Farakka Barrage will become immaterial, if erosion continues at this rate. Also the sole land link between most of India, particularly southern India, south Bengal, north

Bengal and Assam, which is the Farakka Barrage, will be cut, It is going to be a catastrophe of major proportions. But unfortunately, because it is a peculiar problem of a particular State in a little distant part of the country, I have never heard or discussed it or raised it in this House. The Government of West Bengal has been representing to the Central Government time and again for three things. The first demand is to declare erosion of the Ganga, the Padma as a national problem because it is a national problem. It may not have that impact in Delhi as you have events in this part of the country, but it is a national problem; it is an urgent problem and it is getting worse day by day. The second demand of the West Bengal Government is to create adequate mechanism for dealing with this erosion. The third demand of the West Bengal Government has been to allocate adequate resources to stop the erosion of this river; erosion of Indian territory and, more or less, donating the Indian territory to Bangladesh.

' Now, way back in 1996, the Planning Commission set up an expert committee under Mr. J.R. Keshkar, and the Planning Commission, at that time, in 1996, had allotted a sum of Rs.927 Crores. Given the normal inflation between 1996 and now, I would imagine, as a very amateur kind of a guess, a very rough guess, it will now be Rs.1200-1500 Crores. Unfortunately, in spite of repeated representation by the West Bengal Government, the Centre has so far released very, very minimal amount of money to deal with this problem, and these have been released to deal with this major problem on the issue of short-term measures only like putting some earth, putting some sand, putting some other temporary measures, which sooner they are put in they are washed away. And, every year, at least right from 1990 onwards, the Central Government has been saying, "It cannot be done in the monsoon time. So we will deal with it in the next monsoon". But by the time the next monsoon comes, there is no work done. It is happening again this year. So, I don't think the short-term » patchwork measures will have any effect. I think what is required is a complete system of river training works for this entire stretch for the Ganga and Padda rivers as also the Bhagirathi which is flowing Southwards. This, I think, cannot be done with this Rs.1200 or Rs.1,500 Crores; it will take much more. I think this catastrophe which is taking place in West Bengal is not being addressed by the Centre with due seriousness. I am aware that at this moment we have got the hon. Minister of Food and Agriculture present here. But this problem pertains to the Ministry of Water Resources. So, I would request him, through you, to convey our sentiments

from West Bengal to the Ministry of Water Resources whose Minister, incidentally, happens to come from the same part of the State. In addition, Ganga-Paddha is not the only problem...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Would you be finishing now?

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY: Yes, Sir; just one minute more.

There is a complex of rivers in South Bengal. The rivers of Hooghly, Bhagirathi and Ichhamati have their own problems. The Bhagirathi is also eroding all the way down from Farakka almost to Kolkata where it becomes Hooghly. Strangely enough, the Bhagirathi, as it goes past Kolkata, becomes Hooghly, which is silting up. This is a major, major hydrological problem, and I don't think these piecemeal efforts which we are making to address this problem is going to have any effect. So, I would request, through you once again to the Centre, to kindly declare Ganga-Padda erosion as a national problem; kindly create an adequate authority and a mechanism to see that these plans are put into action, and kindly allot the resources required. Do not put off this threat because a day will come when you will have the two parts of the State totally cut off from each other, and that catastrophe must not be allowed to happen.

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, I want to take advantage of the presence of the Minister of Food and Agriculture and confine my remarks to four or five issues arising out of the performance of this year's monsoon because what we are discussing is the flood and drought which after all reflects the performance of the monsoon. So, I want to raise three or four issues which arise out of the performance so far. Many of these issues, of course, go beyond the purview of the Ministry of Food and Agriculture. They concern the Ministry of Science and Technology. But, through him, I want to make the Government aware of some of these questions that have arisen. Sir, first, when trying to make a sense of what the performance of the monsoon has been so far, in the public domain, the data is available only up to the 20th of July. Last night, after a considerable amount of effort, I was able to locate a map of India which shows cumulative performance of the monsoons this year from the first of June to the 20th of July. Sir, when you look at this map, as far as all-India is concerned - and, of course, Mr. Pawar may have this map as of

yesterday, but I have this map only as of 20th July from the website of the Indian Meteorological Department -- it is true that for India as a whole, the monsoon appears to have been normal this year. The Minister has also gone on record as having said that the all-India picture shows a normal monsoon in 2005 as opposed to somewhat deficient monsoon in 2004. However, Sir, if you look at the State-wise picture, there are a number of areas where the monsoon this year has indeed been substantially deficient so far. Sir, Bihar, Jharkhand, Orissa, Assam and Meghalaya — in fact, the entire North-East minus Arunachal Pradesh - and coastal Andhra are areas where there has been a very substantial shortfall in the monsoon rains this year as compared to the normal. Till last week, the eastern UP. was in this category, but based on the latest data, it appears that the cumulative rainfall in the eastern UP. is normal. So, it is Bihar, Jharkhand, Orissa, coastal Andhra and the entire North-East minus Arunachal Pradesh. And I should mention Marathwada also as an area which has been seen substantial deficiency.

So, my first submission to the Food and Agriculture Minister is — he monitors the monsoon on day-to-day basis - while the all-India picture is satisfactory, when you de-segregate this at the level of the State - and at the level of the State also, Sir, it is very unsatisfactory - you really have to go down to a lower level, but that is not possible with today's information. At the level of the State, there are still very large numbers of areas which are showing significant shortfall in rains this year as compared to the normal. My question to him really is this. What is the impact that this is having on agricultural production? Sir, if you look at the foodgrain stocks, as of 1st July, the optimum norm tor rice is 10 million tonnes and the optimum norm for wheat is 17 million tonnes. As opposed to this, on the 1st of July this year, the actual foodgrain buffer for rice is 10 million tonnes and the foodgrain buffer for wheat is 14.5 million tonnes. In other words, we are okay as far as rice buffer is concerned, but as far as wheat buffer is concerned, we are lower than what is recommended as desirable. Now, of course, there will be procurement from now on and the foodgrain stocks are bound to build up. But what I would ask the hon. Minister is this: given this regionally different performance in monsoon, does he expect any effect on the procurement of foodgrains particularly and whether, in fact, he expects some impact on oilseeds and pulses which often tend to get neglected in our discussions, in our preoccupation with foodgrains?

Sir, my second question is on the monsoon itself. And I am glad that the distinguished scientist, Dr. Kasturirangan, is present here because one of the points that I do want to raise concerns the institute to which he belongs, the Indian Institute of Science. Sir, it is a fact that in the last few years, the track record of monsoon prediction in this country, the track record of predicting whether this region is going to have floods or that region is going to have drought has come under severe stress and questioning. We know for a fact that the drought of 2002 was not predicted; the good performance of the monsoon in 2003 was not predicted; the monsoon shortfall in 2004 was not predicted; and experts have said that even the monsoon performance of this year in terms of prediction leaves a lot to be desired. Sir, last month, in a scientific magazine called *'Current Science',* which is brought out by the Indian Institute of Science, Bangalore, there is an authoritative article called 'Monsoon Prediction: Why Yet Another Failure' by three scientists, who are considered to be the best we have in this business, Sulochana Gadgil, M. Rajeevan and Ravi Nanijundiah. Sir, it is a very detailed analysis of the performance of the Indian Meteorological Department in predicting the performance of the monsoon and thereby the existence of floods and droughts. Sir, I just want to quote the last concluding paragraph of this analysis. This says, "Our analysis of the predictions generated by the empirical models used operationally by the Indian Meteorological Department since 1932..." Sir, this is very important, "Our analysis of the predictions generated by the empirical models used operationally by the Indian Meteorological Department since 1932 suggests that the performance of these models based on the relationship of the monsoon rainfall to atmospheric or oceanic conditions over different parts of the globe has not been satisfactory." Sir, there is a worse indictment to follow. It goes on to say, "They have not been improved over eight decades, despite several changes in the operational models and better understanding of monsoon variability." Sir, the scientific conclusion is that all the models that we are using today are highly unsatisfactory, do not lead to any reliable or robust predictions of the monsoon and, therefore, we are not in a position to assess which regions are going to be prone to floods and which regions are going to be prone to droughts in a particular monsoon situation. So, Sir, my request to the hon. Minister is that since he really is the nodal point to review the monsoon performance and he gets the data on a day-to-day basis from the National Centre for Medium Range Weather Forecasting, whether he would be in a position to take a leadership role and -bring about a very substantial upgradation in the technical capacity, in the

scientific capacity of the Indian system to understand the monsoon performance pattern.

Sir, we are a major nuclear power; we are a major IT power; we are a major bio-technology power, but if we are unable to predict in a reliable and robust manner such a basic thing like the Indian Monsoon which is so central to the existence of India even today, I am afraid, Sir, much of our scientific and technological expertise would not have much meaning to the large sections of our population. So, my second request to the Minister would be to have a look at what the scientific assessment of the monsoon model is really today. There is a consensus that it has not served us. If it has not served us well, where do we go from here? Is it still going to be a gamble; is it still going to be fire-fighting next year — fire-fighting for floods and fire-fighting for droughts in some other regions?

Sir, my third point which I would like to raise relates to the recommendations of the Twelfth Finance Commission and go directly to the short term issue of flood and drought that the States are facing. Gujarat, Madhya Pradesh, Himachal and Uttaranchal have faced severe problems of floods. Mr. Vikram Verma raised the question of flood relief for Madhya Pradesh. The speakers from Gujarat raised the question of flood relief for Gujarat. Sir, what I would like to ask the hon. Minister is this. That the Report of the Twelfth Finance Commission which was submitted some months back, during the Budget Session, made a large number of far-reaching recommendations concerning calamity relief. It made recommendations relating to the Calamity Relief Fund (CRF); and it made recommendations relating to the NCCF, the National Calamity Contingency Fund. It made recommendations both on the financing of these mechanisms, and more importantly, in the working of these mechanisms to make it much more effective. Now, for example, Sir, just to take a point that my senior colleague Mr. Vayalar Ravi had made and just to buttress the point that he made, in para 9.12, the Twelfth Finance Commission says, "We find considerable justification in widening the list of calamities which may be covered by our recommendations". The definition of natural calamity as applicable at present may be extended to cover landslides, avalanches, cloudburst and pest attacks. Avalanches, we know, Sir, was a very natural calamity that overtook the State of Jammu and Kashmir some months ago. And so on and so forth. Sir, the point I want to make is that a large number of operational recommendations which were made by the Twelfth Finance Commission relating to the size of the Calamity Relief Fund, relating

to the size of the National Calamity Contingency Fund, and the manner in which these two funds would be operated, I would like the hon. Minister to enlighten us on whether these recommendations have been accepted by the Government, and whether these improvements that have been suggested by the Twelfth Finance Commission have actually been put into practice.

Finally, Sir, I would say that every time we have a discussion on floods and drought, the issue of inter-linking of rivers is raised. And I would like to reiterate that this is an issue that is fraught with grave political, ecological and social consequences and we should hasten slowly in the matter in spite of the enthusiasm that has been shown by many people, by many scientists, by many distinguished technocrats whom I will not name--they have expressed support for the scheme--but I do believe that the weight of technological, economic and ecological opinion is that we should hasten slowly. There may well be place for inter-linking of specific rivers like the Ken and the Betwa, as put out by the Ministry of Water Resources but to imagine that we are going to be able to solve our annual problems of floods and drought by a massive programme of inter-linking of rivers, in my view, Sir, there would be no greater calamity than massive inter-linking of rivers. Thank you.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Thank you very much, Mr. Vice-Chairman. Some time back, in reply to a supplementary on a Starred Question, the Minister for Science and Technology had made a statement in this House that the present system does not permit us to make week-by-week and district-by-district prediction of the rainfall. I had proposed a Short Duration Discussion on that matter, and since it has not turned up, I am going to take advantage of today's discussion on the drought and flood situation to raise some of the points I raised there, particularly because Mr. Jairam Ramesh happened to have raised some of these points now.

The discussion is taking place towards the end of July and, therefore, we are discussing flood and drought. If the discussion had happened towards the mid-June this year, then we would have probably discussed only drought. Because it was at that time, that the Prime Minister had called even an emergency meeting in order to examine how to face drought and famine situation in the country. Later on, the rains came; all the same, whereas the Indian Meteorological Department had predicted an excess of 19 per cent in the month of June, the estimate was revised to (-)34 per cent by the same institute in Bangalore. Consequently, the estimates of the crop

were generally scaled down, and after the rain situation improved, recently the Minister for Food and Agriculture made a statement that the situation was satisfactory and the situation of agricultural commodities would be very good.

But what requires to be discussed is not so much the disaster caused by the floods, or the sufferings caused by the drought. What is important is, whereas for the country as a whole the rainfall is generally satisfactory, particularly if you take into account the availability of water in countries like Israel, why is it that we are facing the problem of coexistence of floods and drought in the same country? Coexistence both in the time dimension and in the space dimension. As of today, in some States, so many people have said, there are floods, in others there is drought. In the month of June we were facing an acute situation, a threat of famine and now we are facing a situation which is quite different.

I had proposed that the disasters should not be used as an instrument for refurbishing State-finances. R.K. Laxman's famous cartoon shows, in a particular area "famine relief fund" banner being replaced by "Flood relief fund." Either way, I think, there is a matter of encroachment on river beds which results in flood disasters and there are some regions which are perennially drought-affected.

The important thing in today's epoch of knowledge is, do we have knowledge of that and if we have knowledge, I think, adequate measures can be taken by both the farmers and other people who have stakes in regular rainfall to protect themselves. As the Minister for Science and Technology himself stated, 'we do not have any system of prediction which can give week-by-week and district-by-district forecast of rain.' If that is the situation, I would say, a big question arises about justification of continuation of the Meteorological Department itself as far as agriculture is concerned because farmers are not interested in the annual averages or in the national averages. The crops depend upon actual day-to-day, week-to-week rainfall. If the rainfall is not there, he wants the rainfall and once the rains start coming, he wants the rains to stop. That is the situation in agriculture. As far as agriculture is concerned the question is: Is there sufficient degree of confidence that can be put in the meteorological prediction? It is understandable that we do not have that system. I have seen in many countries like Australia, for example, on the radio they are giving week-by-week and even tehsil-by-tehsil prediction, or that kind of a block. Not only prediction, the radio also gives advice to the farmers on the

necessary steps that they have to take. Similarly, when we are flying in by air, we are told what kind of weather to expect at the destination. If that is possible, then, I have a feeling that the meteorological department does not have the kind of personnel that is necessary for making prediction that are relevant to agriculture who have some kind of a personal knowledge of agriculture.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI FALI S. NARIMAN): Mr. Sharad Joshi, we have four more speakers.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Just two more minutes. Mr. Vice-Chairman, the more important thing is, unpredictability is understandable but to cover up that unpredictability and to pretend that we have acceptable and practicable knowledge of it is even more serious. I am referring to a scheme announced by the Finance Minister recently; it was vaguely called the 'weather insurance' or 'rain insurance'. And the questions that were raised were: One. Are farmers to be the only premium payers for such insurance? Question no. two was, do we have the necessary morality tables on the rain, or, on weather that are necessary for calculating the exact premia; and if the premia, as the Finance Minister announced to all, three per cent, then, I think, that is a gross underestimate of the unpredictability of monsoons in India. Firstly, co-existence of drought and flood is the problem and the more important thing is to have knowledge about what is going to happen, at least, over a short period of time. But in any case if you can't do that, then, the Finance Minister should not have misled the nation by promising a weather insurance which is neither scientific, nor practical nor a proper commercial business proposition. Thank you very much.

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम इस सदन में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न प्रदेशों में बाढ़ और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश, जो एक छोटा-सा पहाडी प्रदेश हैं, उसमें सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां बहती हैं, लेकिन इन नदियों का इतिहास कभी-भी बाढ़ का इतिहास नहीं रहा हैं। किन्तु सतलुज नदी में पिछले दो-तीन वर्षो से जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही हैं, उसके कारण न केवल हिमाचल प्रदेश वरन् पूरे हिन्दुस्तान को खतरे का सामना करना पड़ सकता हैं। हम सभी जानते हैं कि सतलुज नदी पर भाखड़ा डैंम बना हुआ हैं, जिसे हिन्दुस्तान के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लोकर्पण करते हुए कहा था कि यह हिन्दुस्तान का आधुनिक मंदिर हैं, लेकिन 2001 में सतलुज नदी में पहली बार बाढ़ आई, रात के अधेरे में अचानक बाढ़ आई, जिसमें सैकड़ो जानें चली गई और करोड़ो रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई, लेकिन यह मालूम नहीं हो सका कि उस समय अचानक यह बाढ़ की स्थिति उस नदी में क्यों उत्पन्न हुई । 2004 में पारछू झील, जो कि तिब्बत

में स्थित हैं और तिब्बत चीन के अधीन क्षेत्र हैं और उस पारछू झील से सतलुज नदी की जो सहायक नदियां हैं, वे बहती हैं , उनका उद्गम स्थान पारछू हैं। उस पारछू झील में पिछले वर्ष लैंड स्लाइड के कारण उसका उद्गम स्थान बंद हो गया हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और लगभग 4-5 महीनों तक हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों के लोगों को ऊंचे स्थानों पर बसाना पड़ा था। उसके बाद सर्दी का मौसम आया और वहां पर बर्फ होने के कारण पानी की स्थिति कम हो गई, इसलिए यह कहा गया कि अब यहां पर बाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। लेकिन इस वर्ष जून माह में जब गर्मी का मौसम फिर से आया तो उस सतलुज नदी में दिन के समय लगभग 35-40 फुट जल स्तर बढ़ गया, जिसके कारण आज भी हिमाचल प्रदेश का जो तिब्बत के साथ लगता हुआ जिला किन्नौर हैं, वह बंद पड़ा हैं, वह सारी दुनिया से जमीन के रास्ते से कटा हुआ पड़ा हैं । माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि भाखड़ा डैम इस पर स्थित हैं। इसी नदी के ऊपर हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा जल विद्युत का प्रोजेक्ट नाथपा-झाकडी प्रोजेक्ट जिसका लोकार्पण पिछले महीने ही प्रधान मंत्री ने किया हैं, वह भी स्थित हैं और अनेकों जल विद्युत परियोजनाएं इस नदी के ऊपर बनने जा रही हैं। इसी वर्ष जो बाढ़ की स्थिति एक दिन में हुई उसके कारण जो नाथपा-झाकडी प्रोजेक्ट हैं, उसमें रोजाना 9 करोड रुपए का नुकसान एस0जे0पी0सी0- सतलुज जल विद्युत निगम जो हिन्दुस्तान और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम हैं, उसको हो रहा हैं और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की जनता आज भी दुनिया के बाकी भागों से कटी हुई हैं, उनकी नकदी फसलों का मंडियों तक पहुंचना अंसभव हो गया हैं। वहां पर आज भी लोगों को 35-40 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता हैं। हिन्दुस्तान के गृह मंत्री और यू0पी0ए0 की चेयरपर्सन हेलीकोप्टर पर वहां का हवाई सर्वे करके आई हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की उन सड़कों को, जो बोर्डर का भी इलाका हैं, जहां पर सेना आवागमन भी होता हैं, आज भी उन सड़को को बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो पा रहा हैं। हिमाचल प्रदेश की उस बाढ़ के कारण जो 900 करोड़ रुपए की एसेस्मेंट हुई हैं कि इतना नुकसान हुआ हैं, लेकिन उसमें से केवल 37 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया जाएगा, इस बात का ऐलान किया गया हैं ।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात की ओर इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि इस नदी पर जो यह बाढ़ आ रही हैं क्योंकि सतलुज नदी का इतिहास कभी भी बाढ़ का इतिहास नहीं रहा हैं, क्या यह बाढ़ जो एकदम से अचानक किसी समय आ जाती हैं और एक दिन के लिए आती हैं और इतनी तबाही कर जाती हैं, क्या यह आर्टिफिसियल काम तो नहीं हैं और वहां पर अगर उस झील में पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाए और वह पानी वहां से बह जाए तो भाखड़ा डैम नहीं बच सकता हैं और यदि भाखड़ा डेम को नुकसान होता हैं तो हिन्दुस्तान के जो बहुत समृद्ध प्रांत हैं- पंजाब और हरियाणा, उनको भी नुकसान हो सकता हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह हैं कि इस बारे में सदन में पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी, लेकिन आज तक चीन की गवर्नमेंट के साथ हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट नें कोई सम्पर्क नहीं किया हैं और क्या हिन्दुस्तान की कोई एक एक्सपर्ट टीम जैसा पिछले वर्ष कहा गया था कि वह उस स्थान का मुआयना करने जाएगी । बार-बार जो मीडिया के द्वारा बताया जा रहा हैं कि चीन की सरकार हिन्दुस्तान की टीम को वहां पर जाने के लिए तथा निरीक्षण करने के लिए एलाउ नहीं कर रही हैं। तो इस बारे में उच्च स्तर पर हिन्दुस्तान की सरकार को विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीन की सरकार के साथ बात करके इसका हल निकालना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो लैंड स्लाइड हो रहे हैं, जो जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं उनके कारण लारी इकोलॉजी और एन्वायरेंमेंट पहाडों का खराब हो रहा हैं। इसके अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग़ का एक महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, जिसके कारण गिलेशियर बिना किसी समय के बहने प्रारम्भ हो गए हैं, टूटने प्रारम्भ हो गए हैं और उससे भी बाढ़ की स्थिति खास करके जो उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश हैं, उनमें उत्पन्न हो रही हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में सदन में आपके माध्यम से निवेदन हैं कि हिन्दुस्तान की पिछली सरकार ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधान मंत्री थे तो एक हिमालयन डवलपमेंट आथॉरिटी की चर्चा की थी और उसका काम प्रारम्भ किया था। मेरा वर्तमान सरकार से भी निवेदन हैं कि इस प्रकार से सारे प्रदेशों के जो नॉर्थ ईस्ट प्रदेश भी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के भी प्रदेश हैं, इनके समग्र विकास के साथ-साथ इसमें जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती हैं, इकॉलोजी की स्थिति उत्पन्न होती हैं, एन्वॉयरेंमेंट की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो रही हैं, इनको ठीक करने के लिए इस प्रकार की अथॉरिटी का गठन किया जाए ताकि इन प्रदेशों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो और सतलुज , रावी और व्यास में जो इस प्रकार की बाढ़ आई हैं, जिसके कारण प्रदेश की स्थिति खराब हो रही हैं, इसलिए हिन्दुस्तान की केन्द्र सरकार को अधिक से अधिक सहायता हिमाचल प्रदेश को देनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पूरे देश के एनवायरंमेंट की और इकोलॉंजी की रक्षा करता हैं। इसी के साथ बाकी प्रदेशों की समृद्धि के लिए सारा पानी हिमाचल से बहता हैं और उस पानी का उपयोग पंजाब और हरियाणा में होता हैं, उस पानी से हिमाचल में कोई सिंचाई नहीं होती हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या हैं और इसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत –बहुत धन्यवाद ।

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Sir, at the outset, I associate myself with the views expressed by the hon. Members of this House regarding the flood situation in various parts of the country. I was very patiently hearing the views of the hon. Members on the flood and drought situation. But, unfortunately, the State of Maharashtra has not figured in the whole discussion. Therefore having associated myself with the views expressed by the hon. Members regarding the affected areas and the persons, I would like to bring to your kind attention the present situation of Maharashtra. It may or may not be circulated today, the headlines in the newspapers have been that the whole Konkan division is under floods. In all the three districts of Konkan, that is, Raigarh, Ratnagiri and Sindhudurg are flooded. It had rained continuously for forty hours. I do not know what is the situation today, but on 24th and 25th, it had rained continuously in the Konkan division. You can well imagine the disastrous effect of the

5.00 P.M.

continuous rains on crops, houses, people, etc. I, therefore, would like to bring it to the notice of the hon. Agricultural Minister that the recent flooding of Konkan is a matter of great concern for both, the State Government of Maharashtra and the Central Government. There was a drought in Vidarbha, particularly in the Yavatmal district. The casualty has been very high. Thousands of people have become homeless. I take this opportunity to request the hon. Minister to extend financial help to Maharashtra.

The situation in Maharashtra is, that monsoon was delayed by 15-20 days, and the distribution of rain has been very uneven. Konkan, Western Maharashtra, Eastern Vidarbha and some of the districts of North Maharashtra, adjoining Gujarat, received good rains, but rest of the districts of Maharashtra received below average rainfall. Sir, I do not want to take much time of the House. The situation is that in about 16 districts of Maharashtra, the position concerning crop sowing is like this. In Jalgaon, Ahmednagar, Solapur, Aurangabad, Jalna, Beed and Latur, the sowing percentage is zero. In Usmanabad, it is hardly 9.20 per cent. Sir, again, Nanded, Parbhani and Hingoli, it is zero per cent. In Buldhana and Akola it is 0.1 per cent. In Washim and Amravati it is zero per cent. In Yavatmal, it is 11.1 per cent. This is an indication of the drought situation. It is concealed; it is not opened before the Press. This is the exact situation in Maharashtra.

Sir, we are discussing a contrast situation. It is contrary in the sense that we are discussing the flood situation, and, at the same time, we are discussing the drought condition also. In Maharashtra, the real phenomenon this year is that drought is there and flood is also there. Maharashtra is facing both the contrasts, that is, flood and drought. Sir, this clearly indicates that the present deficiencies in rainfall may not be compensated even by increased rainfall in the later part of July and August. We are discussing this issue in the month of July. So, any amount of prospective rain will not compensate for the damage which has already occurred during this period.

The team which visited Maharashtra recommended assistance to the tune of Rs. 103 Crores through the National Contingency Calamity Relief Fund. The fund has not been received. I want to bring it to the notice of the hon. Agriculture Minister that there is scarcity of water, fodder, cattle camps etc. These are the drought problems being faced by Maharashtra.

Sir, at the end of May, 2005, the total labour attendance under the Employment Guarantee Scheme (EGS), the Food for Work Programme, and the Sampoorna Gramin Rojgar Yojana is to the tune of 11 lakhs. It is the daily attendance. This indicates the gravity of the drought situation in Maharashtra.

Sir, I do not want to take much time of this House in explaining various schemes implemented for scarcity, mitigation and natural calamities during 1st April, 2003 to July, 2005, but I will switch on to the current year. There are no uniform norms for Maharashtra. That is the gimmick. The Southern part of Maharashtra is always supposed to have deficit rainfall. This time, it is at its maximum. Of course, Mumbai is fortunate enough because with the arrival of monsoon the ground water level has risen and the water problem is solved. Normally, monsoon arrives in Vidharbha and Maharashtra. This time Vidharbha - Maharashtra are left far behind. Even in the Central part of Maharashtra, I now conclude, that the estimate to face the drought condition in Maharashtra has been worked by the Government of Maharashtra.

So, they sent a Memorandum to the Government of India. They requested and demanded the Central Assistance as follows: Agricultural subsidy: Rs.300 Crores; Water Supply: Rs.100 Crores and Fodder Depots: Rs. 100 Crores. Therefore, the Government of Maharashtra sent a Memorandum to the Government of India requesting for an assistance to the tune of Rs.500 Crores. I saw the exhaustive interview of the hon. Agriculture Minister regarding the monsoon situation and the crop situation in the country. I am satisfied with his interview. The issues which have been raised by Mr. Joshi and Mr: Jairam indicate perspective planning of agriculture. I don't want to touch it. But what I could observe from his interview was that he was hopeful. No doubt, he was apprehensive of the shortage of cereals, but, overall, he expressed his satisfaction. I must request him that instead of discussing the contrast situation of floods disaster and drought, we must have a permanent solution and perspective planning. Thank you.

DR. A.K. PATEL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, whether it is this House or the other House, the subjects of drought and flood are discussed every year. In spite of repeated discussions and so many suggestions, till today, no permanent solution has been found out yet. I think, Planning Commission should plan in such a way that such calamities could be tackled very well. Sir, I restrict myself to Gujarat State only.

Repeatedly, Gujarat has been facing calamities for the last ten years. Gujarat had very bad cyclone; Gujarat had very bad earthquake; and, this year, the heavy rain which poured only for a week has created many problems. Out of 25 districts, 11 districts were very badly affected. And, about 85 per cent of the annual rain poured only in a week. So, we can imagine the situation. That heavy rain caused so many problems. All the rivers got over-flooded, particularly, in the areas, like *Madhya* Gujarat, which is known as Vadodara district, Surat and Wapi. The Gujarat Government had made Disaster Management Programme some time back. I think, because of that project and programme, the Gujarat Government could face the situation fairly well. More than 200 people died because of these heavy rains. About 7,000 villages were badly affected because of disruption in supply of electricity. Because of heavy rains, many power projects went out of order. About 1500 panchayat roads and 262 State roads were damaged very badly. Luckily, the Army, which was deployed, helped a lot. Army helicopters also helped a lot. In this way, mortality rate could be decreased, I would say. I congratulate the Army people who did a tremendous job, in a commendable way. The Gujarat Government has submitted'details of damages caused due to floods, and it is worth Rs. 8000 crores. Through you, Sir, I request the Government of India to provide the maximum help which is possible. Sir, particularly, the National and State Highways in the State are very badly damaged. Gujarat is having the first Express Highway, and most of that road area has been washed away. I think, it is necessary to reconstruct it immediately so that smooth flow of traffic can be maintained there.

Sir, Gujarat also had a very good project in the past. Check-dams were constructed in some parts of Gujarat, particularly, in Saurastra. More than 18,000 check-dams were constructed. That solved the problem of water retention. But this year due to heavy rains, most of check-dams have been washed away; and now the Gujarat Government again has to spend a lot of money for checking the water being flown away to sea. Sir, since a lot of things have already been said by my colleague from Gujarat, I would restrict myself here and would not go into other details. The only thing I would like to say is that Gujarat had received only Rs. 92 crores towards the National Calamity Fund, and it has spent more than Rs. 250 crores in cash doles and in other forms. So, Sir, through you, I request the Government of India to give money to the Gujarat Government as early as possible and do whatever maximum it can.

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा): मान्यवर, यह मुल्क कृषि प्रधान मुल्क हैं। हम प्रतिवर्ष बाढ़ और सूखे को फेस करते हैं । इस सम्मानित सदन में, दूसरे सम्मानित सदन में और राज्यों के सम्मानित सदनों में चर्चा होती हैं, परन्तु इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा कि क्या सरकार कभी पिछले दस सालों में बाढ़ और सूखे के लिए जितना पैसा दिया हैं, जितना पैसा राहत के लिए दिया हैं, क्या कभी उसकी गणना, उसका आकलन और फिजिकल वैरिफिकेशन कभी कराने का काम किया हैं? मान्यवर, सत्यता यह हैं कि सूखा पड़ता हैं । सूखे की सहायता के लिए पैसा रिलीज हो जाता हैं और सूखे में मरता हैं गावं का किसान और गरीब मजूदर । सूखे के कारण किसान और मजदूर बेघर हो जाते हैं और बाघर हो जाता हैं बड़ा अधिकारी । मान्यवर,पहले सूखे के लिए पैसा ले लेते हैं, फिर इसके बाद बाढ़ आ जाती हैं । सूखे में बंधा बनता हैं, रोजगार के लिए पैसा मिलता हैं । सूखे में जो बंधा बनाया जाता हैं, जब बाढ़ आ जाती हैं तो कह दिया जाता हैं बधां बह गया । मान्यवर, इस मुल्क में कितने गौतम काम कर रहे हैं ? आज केवल अनुदान मांगने से, बजट मांगने से काम नहीं चलेगा । आवश्यकता इस बात की हैं कि जो पैसा आपने किसाने की मदद के लिए, मजदूर की मदद के लिए, जनता की मदद के लिए मुक्त किया हैं, चाहे वह पैसा प्रदेश सरकार की ओर से हो, चाहे केन्द्र सरकार की सहायता से हो, उस पैसे का सही उपयोग कितना हुआ हैं ? इस मुल्क में गौतम का मामला सब के सामने हैं, फिर भी हम उसके ऊपर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं । मान्यवर,मेरा आप से अनुरोध हैं कि आप इस मामले में सरकार को निर्देशित करें, यह अकेले खाद्य और कृषि मंत्रालय का काम नहीं हैं । इसमें प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की एक कमेटी बनाकर, स्थाई समाधान के लिए कार्य होना चाहिए । इस स्थाई समाधान में सीधे किसान को मदद होनी चाहिए । जब तक किसान को सीधी मदद नहीं मिलेगी उसका भला नहीं हो सकता । दुकानों पर सब दवाई नही बिकती हैं, जैसे ही बाढ़ आई, बाढ़ के नाम पर फर्जी दवा की खरीद हो जाती हैं । यह दवा कहां गई, किसी को कुछ पता नहीं चलता । पेय-जल की व्यवस्था हो गई । पेय-जल टैंक में था, हवाई जहाज में था या रेल में था इसकी किसी को जानकारी नही होती । किसी हैंड पम्प की स्थापना तो होती नहीं हैं, लेकिन पेयजल की व्यवस्था हो जाती हैं । इस प्रकार यह लगातार चलता रहताहैं । बाढ़ भी आधी जनता को बड़ा आशीर्वाद देती हैं । आशीर्वाद इसलिए देती हैं कि गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब शहरी, जिसका रोजगार चला जाता हैं, जिसकी फसलें तबाह हो जाती हैं, वह बेघर हो जाता हैं और कितने ही गौतम बाघर हो जाते हैं । मान्यवर,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे यह बताने का कष्ट करें जब वे इसके उत्तर में अपना भाषण दें, उन्होंने कितनी बार फिजीकल वैरीफिकेशन कराया हैं और जो पैसा राहत के लिए गया हैं, वह कितना जमीन तक, कितना किसान और कितना मजदूर तक गया हैं ? मान्यवर, हमारे स्टेट में अभी उत्तरांचल और हिमाचल की जो चिंता हैं, उससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं । अगर गुजरात में, मध्य प्रदेश में बाढ़ आती हैं तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड भी प्रभावित होता हैं ।यही नही अगर हिंदुस्तान के एक भी स्टेट में बाढ़ आती हैं तो वहां का किसान तबाह होता हैं, वहां की फसलें तबाह होती हैं । इसका असर पूरे हिंदुस्तान पर पड़ता हैं, इससे पूरे हिंदुस्तान की मार्किट डिस्टर्ब होती हैं । इसे रोकने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना चाहिए । आस्ट्रिया एक छोटा सा देश हैं । आस्ट्रिया में एक सप्ताह पहले बता दिया जाता हैं कि

इतनी बरसात होगी, लेकिन हमारे यहां टेलीकास्ट हैं ही नही । इसका कुछ न कुछ तो आप लोगों को उपाय करना चाहिए । सरकार को यह निर्देश देना चाहिए कि इसका सीधा-सीधा स्थायी समाधान निकालें । मान्यवर, उच्च स्तर पर सूखे से निपटने के लिए आपको चिंता करनी चाहिए, सरकार को चिंता करनी चाहिए ।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

आज भूजल स्तर, आपके मुल्क का जो सधन कृषि क्षेत्र हैं, उत्तर भारत का जो भूजल स्तर हैं, वह स्तर रोज नीचे जा रहा हैं । नदियों पर चेक डैम बनाने की बात हुई । हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृष्णा, हिंडन और काली नदी पर चेक डैम बनाने की बात थी, आज तक कोई चेक डैम नहीं बना । जिस क्षेत्र में बीस फुट, चालीस फुट पर ट्यूबवेल लगती थी, आज 120,200 फुट पर वही टयूबवेल्स लग रही हैं । मान्यवर, बाढ आई, गंगा ने उत्तरांचल को , पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया । चाहे मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, बिजनौर हो, हरिद्वार हो, सारे जिले इससे प्रभावित हुए हैं । इसे रोकने का क्या प्रयास किया हैं ? पैसा चला जाता हैं । इसका सकारात्मक परिणाम होना चाहिए । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पैसे से जहां तात्कालिक राहत की बात करते हैं, उसके साथ-साथ इसके स्थायी समाधान की व्यवस्था भी की जानी चाहिए । फिजीकल वैरीफिकेशन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए कराया जाना चाहिए कि पिछले साल जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, वह बह गई या रह गई । धन्यवाद ।

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभापति जी, बाढ़ और सूखे के बारे में लगभग हर वर्ष हमारी चर्चा होती हैं और चर्चा होने के बाद केन्द्र सरकार के द्वारा उन राज्यों को, जिन राज्यों में भयंकर बाढ़ या सूखे की स्थिति होती हैं, उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जाती हैं । अगर हम देखें तो सन् 1952 से लेकर आज 2005 हैं, इन तिरेपन वर्षो के अंतराल में विज्ञान के क्षेत्र में , तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई हैं, लेकिन जब कभी भी बाढ़ और सूखे की स्थिति का हमें मुकाबला करना होता हैं तो मैं समझता हूं कि दुनिया के तमाम देशों की तुलना में हिंदुस्तान पीछे नहीं हैं । यह विज्ञान के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भी पीछे नहीं हैं । आखिर हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता हैं कि हमारे मौसम विभाग के द्वारा जो बाढ़ आने की सूचना दी जाती हैं, उस पर लोग कितना विश्वास करते हैं । लोग चाहे विश्वास करें या न करें, लेकिन जो सरकारी अमला हैं, उस सरकारी अमले को पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए कि बाढ़ की स्थितिसे निपटने के लिए हमें कौन-कौन से उपाय करनें होंगे और कौन-कौन से उपाय करने के बाद लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती हैं ।माननीय उपसभापति, मेरा यह अपना अनुभव हैं और मैंने स्वंय इस बात को देखा हैं कि हम जिस तत्परता से केंद्र सरकार से धनराशि की मांग करते हैं, उस तत्परता से राज्य सरकारें उस राहत राशि को, जो कैलेमिटी फंड से दी जाती हैं, उसका उपयोग हो नहीं पाता हैं । अगर उस बाढ़ पीड़ित इलाके का आप दौरा करके देखें तो आपको अधिकांश लोग कहते नजर आएंगे कि हमें तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं, जबकि केंद्र सरकार से धनराशि दी हैं । केंद्र सरकार की धनराशि दिए जाने के बाद अगर यही हाल हैं तो हमें इसका आकलन करने की नितांत आश्यकता हैं । बाढ़ की स्थिति का जो नजारा हैं, उस संदर्भ में हम इस बात को देख लें कि साउथ ईस्ट-एशिया के समस्त देशों में खाद्यान्न के उत्पादन में निरंतर कमी आ रही हैं । हम इस बात को केवल यह कहकर समाप्त न करें कि इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई हैं और इसलिए अच्छा उत्पादन होगा । उत्पादन तो होगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि हमारे सरकारी भंडारण में

कितना भंडार रहेगा और कदाचित ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था होगी ?

उपसभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी तो अभी बाहर हैं, राज्य मंत्री जी यहां बैठै होंगे, मेरा केवल इतना ही कहना हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रोपर इसकी मोनेटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार तो अपनी हैंसियत के अनुसार अपना कुछ काम करती हैं, लेकिन केन्द्र सरकार से मिलने वाली धनराशि का समुचित उपयोग होना चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि केन्द्र सरकार ने हमारे लिए यह राशि दी हैं और उसका सही इस्तेमाल हो रहा हैं । जहां तक बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का हैं, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को सरकार ने कहां तक माना हैं, किन किन सिफारिशों को स्वीकार किया हैं, इसकी भी जानकारी अगर हमें मिलती हैं,तो उन राज्य सरकारो को उससे लाभ हो सकता हैं। भाई जय राम रमेश ने देश के नक्शे के बारे में कहा कि देश के विभिन्न प्रांतो में किस प्रकार की वर्षा का संकेत हैं, किस प्रकार की वर्षा हुई हैं । चूंकि वे इस बारे में कह चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए । मध्य प्रदेश के करीब नौ जिलो में इस बार भंयकर बाढ़ आई हैं, तीन जिलों में तो काफी संपत्ति का नुकसान भी हुआ हैं और लोगों की जानें भी गई हैं । अगर आप इन जिलों के अंदर देखें, जो मध्य प्रदश में हैं, जैसे रीवा हैं, सतना हैं,सागर हैं, दमोह हैं, पन्ना हैं, कटनी हैं छतरपुर हैं, नरसिंहपुर हैं, जबलपुर हैं ।

श्री वी.नारायणसामी: छत्तीसगढ़ में क्या हुआ?

श्री मोती लाल वोरा: माननीय उपसभापति जी, मुझे मध्य प्रदेश में रहने का सौभाग्य मिला हैं, अनेक वर्षो तक मैं वहां मुख्य मंत्री की हैंसियत से रहा हूं, यह छत्तीसगढ़ तो अभी पिछले तीन वर्षो से बना हैं । छत्तीसगढ़ में भी सूखे की स्थितिसे, बाढ़ की स्थिति से हमें निजात दिलाने की आवश्यकता हैं। तो मैं यह कह रहा था कि इससे जो नुकसान हुआ हैं और नुकसान के साथ जो भारत सरकार ने पहली किस्त दी,वह करीब 95 करोड़ 83 लाख रूपए की दी हैं । यह राशि भाई सुरेश पचौरी जी जब वहां गए थे, तो उन्होंने दी थी । दूसरी किस्त भी भारत सरकार देने की तैयारी में हैं । राज्य सरकार ने जो हेलीकोप्टर की मांग की थी, तो पांच हेलीकोप्टर उनको उपलब्ध कराए गए । मेरा कहने का आशय यह हैं कि राज्य सरकार ने 500 करोड़ रूपए की राशि भारत सरकार से इसके लिए मांगी थी, लेकिन 500 करोड़ रूपए की राशि हरेक राज्य को उसके केवल नौ जिलों के लिए देना संभव नहीं होगा । मेरा इतना ही कहना हैं कि हमें वर्षो और बाढ़ का पूर्वानुमान होना चाहिए , हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए और सरकारी मशीनरी को इस बात का अंदाज होना चाहिए कि किस प्रकार से सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार से बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ेगा । चाहे जिले के अधिकारी हों या प्रदेश के अधिकारी हों, उनको इस दिशा में पूरी तरहसे प्रयत्न करना चाहिए ।

उपसभापति जी,रहा सवाल अन्य प्रदेशो को, तो हिमाचल प्रदेश की बात आपने सुनी, उत्तरांचल की बात आपने सुनी, उत्तर प्रदेश की बात सुनी । जहां तक बिहार की बाढ़ का हैं, बिहार में अकसर जो बाढ़ आती हैं,वह बिहार की अपनी बाढ़ नहीं हैं बल्कि विशेष रूप से नेपाल से जो बाढ़ का पानी आता हैं, उससे हुआ करती हैं । मेरा केवल इतना ही कहना हैं कि भारत सरकार द्वारा जो धनराशि दी जाती हैं, उसकी समुचित रूप से मोनेटरिंग होनी चाहिए और राज्य

सरकार को भी चाहिए कि वह केवल भारत सरकार के ऊपर ही सारी जवाबदारी न डाले । राज्य सरकार की भी अपनी इसमें जिम्मेदारी होती हैंकि जिन लोगों के मकान ढह गए या जहां सड़कें समाप्त हो गई या जहां पुल खत्म हो गए, उनका काम जल्दी से जल्दी करान चाहिए । आवागमन की सुविधांए अगर न हों, तो उससे लोगों को परेशानी होती हैं । बाढ़ के कारण न मालूम कितने महीनों तक लोगों के आवागमन के रास्ते अवरूद्ध हो जाते हैं, इसलिए उन रास्तों को खोलने के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न करें ।

उपसभापति महोदय, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में जो जनहानि हुई हैं, उसके जो आंकड़े मुझे मिले हैं, उसके अनुसार करीब 47 लोगों की मृत्यु हुई हैं और अभी भी वहां डूब के क्षेत्र बने हुए हैं । वहां 4 और 5 जुलाई को भारी बारिश हुई थी और इस 4 और 5 जुलाई की बारिश के बाद करीब 47 लोगों की मृत्यु के समाचार हैं और जो गांव डूब में अभी भी हैं, उससे उनकी संख्या आने के बाद ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं । मेरा केवल इतना ही कहना हैं कि बाढ़ आने से पहले हमारी समुचित रूप से तैयारी होनी चाहिए और सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारी ऐडवांस प्लानिंग होनी चाहिए । कम से कम एक महीना, दो महीने पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सूखे की स्थिति होगी तथा सूखे की स्थिति में लोगों को पलायन न करना पड़े, लोगों को वहां पर काम मिले और जब लोगों को काम मिलेगा तो पलायन नहीं होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ, भारत सरकार ने जिस तत्परता के साथ इस बाढ़ की स्थिति का मुकाबला किया हैं, उसके लिए निश्चित रूप से वह साधुवाद की पात्र हैं । धन्यवाद ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Short duration discussion on the situation arising due to drought and floods in various parts of the country is over. Hon. Ministers for Home Affairs and Agriculture will reply to the debate tomorrow. Now, the House is adjourned till 11.00 a.m. tomorrow, 27th July, 2005.

The House then adjourned at twenty-six minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 27th July, 2005.